

मुख्यमंत्री ने की मेला स्थल पर डोम निर्माण एवं तेलासी-भंडारपुरी मार्ग में स्ट्रीट लाइट लगवाने की घोषणा

गुरु घासीदास बाबा के आदर्शों पर चलकर बनाएंगे विकसित छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री श्री साय भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में हुए शामिल : 162 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 16 विकास कार्यों का किया भूमिपूजन*

गुरु घासीदास बाबा के आदर्शों में ही छिपा है मानवता और समानता का मार्ग : मुख्यमंत्री श्री साय*

रायपुर, लोकशक्ति। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज रायपुर जिले के आरंग तहसील अंतर्गत भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 162 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 16 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, जिनमें नवीन सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने मेला स्थल पर डोम निर्माण, तेलासी-भंडारपुरी मार्ग में स्ट्रीट लाइट लगवाने तथा कुटेसर प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि समाज से पाँच युवा पायलट



बनना चाहें तो उनका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी और उन्हें पायलट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सर्वप्रथम गुरु गद्दी का दर्शन कर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाबा गुरु घासीदास के आदर्शों पर चलकर हमें विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। उनके आदर्शों में मानवता और समानता की सीख निहित है। गुरु बाबा ने समाज को एकजुट होने का संदेश दिया, जिसके

परिणामस्वरूप सतनामी समाज आज प्रगति और सौहार्द की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष भी मुझे मुख्यमंत्री के रूप में इस मेले में शामिल होने का अवसर मिला। लेकिन इस वर्ष और पिछले वर्ष में बड़ा अंतर आया है। पिछले वर्ष जब मैं यहां आया था तब आपके समाज के गुरु श्री खुशवंत साहेब विधायक थे, अब वे मंत्री बने हैं। उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास तथा युवाओं को

कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपके समाज के गौरव से हमें अपार उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता से जो भी वादे किए थे, उन्हें हम 'मोदी की गारंटी' के रूप में पूरा कर रहे हैं। अब तक नौ हजार से अधिक सरकारी भर्तियाँ पूरी हो चुकी हैं और हाल ही में शिक्षा विभाग में पाँच हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि शासन के प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में अनुसूचित जाति समाज के विकास हेतु प्राधिकरण का गठन किया गया था। वर्तमान सरकार ने उसके बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ कर दिया है।

सेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा-

ऑपरेशन सिंदूर-2.0 दूर नहीं



एजेंसी। नमोनिशा मिटा देंगे। राजस्थान के अनूपगढ़ में एक सैन्य चौकी पर बोलते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना इस बार कोई संयम नहीं दिखाएगी। उन्होंने आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता है और आतंकियों की स्प्लाइ बंद नहीं करता है, तो ऑपरेशन सिंदूर-2.0 दूर नहीं होगा। सेना प्रमुख ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में रखा था। इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा की उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल पर जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा।

आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की युवा-केंद्रित विकास योजनाओं का शुभारंभ



एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 4 अक्टूबर को देश के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। वे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे के करीब 62,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की युवा-केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को नए आयाम देने वाला है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर कौशल दीक्षांत समारोह के तहत 46 ऑल इंडिया टॉपस को सम्मानित भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पीएम-सेटु (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन-PM-SETU) योजना शुरू करेंगे। इसके तहत देश के 1,000 सरकारी आईटीआई को 60,000 करोड़ रुपये की निवेश के साथ आधुनिक तकनीक और उद्योग जुड़ी सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

सीएम नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 10-10 हजार

एजेंसी पटना. बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ 26 सितम्बर 2025 को किया गया था. उस दिन राज्य की 75 लाख महिला लाभार्थियों को 10 हजार प्रति लाभार्थी की दर से 7500 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी. आज 3 अक्टूबर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 25 लाख महिला लाभार्थियों को 10 हजार रुपये प्रति लाभार्थी की दर से 2500 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गयी. अब तक कुल 1 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10 हजार करोड़ रुपये

की राशि अंतरित की गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले महिलाओं का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है. यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को दिया जाना है. इसलिए अब जो महिलाएं शेष रह गयी हैं उन्हें 10 हजार रुपये की सहायता राशि देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गयी हैं. अगली तिथि 6 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है।

देश का डेयरी सेक्टर दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला सेक्टर बना : शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का लोकार्पण किया

पीआईबी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कुण्डपाल गुर्जर और केन्द्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के किसानों की दशकों पुरानी अलग सहकारिता मंत्रालय



के गठन की मांग को पूरा करने का काम किया है और इसके लिए पूरे देश की ओर से उनका आभार है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में देश की सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता की नींव को गहरा करने का काम किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2029 तक देश की एक भी पंचायत ऐसी नहीं रहेगी, जहां

एक भी सहकारिता समिति न हो। श्री अमित शाह ने कहा कि आज साबर डेयरी के माध्यम से दूध उत्पादकों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने के प्लांट का काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से ही पूरे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दुग्ध उत्पादों की

जरूरत पूरी होगी। साबर डेयरी ने गुजरात के साबरकांठा जिले से शुरूआत कर 9 राज्यों के दुग्ध उत्पादकों के लिए बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। श्री शाह ने कहा कि गुजरात में त्रिभुवन भाई, भूरा भाई और गलबा भाई ने डेयरियों की नींव रखी और आज कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से गुजरात की 35 लाख बहनें सालाना 85 हजार करोड़ रुपए का व्यापार कर रही हैं। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि साबर प्लांट में प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन दही, 10 मीट्रिक टन योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और प्रतिदिन 10 हजार किलो मिठाई बनेंगे और इससे किसानों की समृद्धि का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि आज हमारी साबर डेयरी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की सेवा कर रही है।

प्राकाश पर्व शर्तों के साथ सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की इजाजत

एजेंसी। भारत सरकार ने गुरु नानक जयंती से पहले एक महत्वपूर्ण फैसले में सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने की शर्तों अनुमति दी है। यह निर्णय 1974 के द्विपक्षीय समझौते के तहत आया है, जिसमें राज्य सरकारों की सिफारिशों पर विदेश और गृह मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के बाद ही चुनिंदा जत्थों को यात्रा की अनुमति मिलेगी। भारत सरकार ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों के लिए सिख तीर्थयात्रियों के कुछ समूहों को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी है। यह यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच 1974 के द्विपक्षीय समझौते के तहत होगी, जो सीमा पार कुछ धार्मिक स्थलों की धार्मिक यात्रा की अनुमति देता है।

इसी महीने शुरू होगी भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा, 5 साल बाद हो रही बहाल

नई दिल्ली/बीजिंग एजेंसी।

भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवाएं पांच साल बाद अक्टूबर के अंत तक फिर से शुरू हो सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। भारत और चीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण इस साल की शुरुआत से दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने और एक संशोधित हवाई सेवा समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। यह भारत सरकार की दोनों देशों के बीच संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य करने की नीति का हिस्सा है।



विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, इन चर्चाओं के बाद अब यह सहमति बनी है कि भारत और चीन के बीच नामित स्थानों को जोड़ने वाली डायरेक्ट फ्लाइट सेवाएं अक्टूबर 2025 के अंत तक शुरू हो सकती हैं। यह शीतकालीन मौसम की समय-सारिणी के अनुसार

होगा, बशर्ते दोनों देशों की नामित एयरलाइंस का व्यावसायिक निर्णय और सभी परिचालन मानदंड पूरे हों।

बयान में आगे कहा गया, नागरिक विमानन प्राधिकरणों के इस समझौते से भारत और चीन के बीच लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे द्विपक्षीय आदान-प्रदान को धीरे-धीरे सामान्य बनाने में मदद मिलेगी। सीधी उड़ानें डोकलाम विवाद के बाद बंद कर दी गई थीं और कोविड-19 महामारी के कारण इसे और आगे टाला गया।

देश पीओके में अत्याचार पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा

‘पाक की सेना निर्दोष नागरिकों के साथ बर्बरता का व्यवहार कर रही’

एजेंसी।

पीओके में पाकिस्तान के अत्याचारों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की है. मंत्रालय का कहना है कि पाक अधिकृत कश्मीर में हो रहा प्रदर्शन पाकिस्तान की दमनकारी नीति और संगठित लूट को दर्शाता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि पाकिस्तान में हामन राइट्स के हन को लेकर सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न भाग है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन की खबरें



देखने को मिल रही हैं. यहां पर पाक सेना निर्दोष नागरिकों के साथ बर्बरता का व्यवहार कर रही है. पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर जवाबदेह ठहराना जरूरी है. जहां पर संसाधन हैं उन हिस्सों में पाकिस्तान का अवैध कब्जा बना हुआ है. यहां पर

व्यवस्थित तरह से लूट है. पीओके प्रदर्शन में अब 12 लोग मरे पीओके में जारी प्रदर्शन और अत्याचार का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है. PoK के राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इस केस में तुरंत दखल देने को कहा है. 29 नवंबर को यहां

आम लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए. उन्होंने प्रदर्शन किया. इसके बाद पाकिस्तानी सेना उन पर फायरिंग शुरू कर दी. इसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है।

पाकिस्तान में चक्का जाम का आह्वान प्रदर्शन के बाद यहां के लोगों ने रावलकोट, मीरपुर, कोटली, नीलम घाटी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अन्य इलाकों में बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। यह PoK में अब तक सबसे बड़ा प्रदर्शन है। अवामी एक्शन कमिटी (एएससी) की अगुवाई में शहबाज शरीफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद से पूरे क्षेत्र में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं पुलिस के अत्याचार शुरू हो गए।

भारत अपना अपमान नहीं सहेगा’ पुतिन ने मोदी को बताया बुद्धिमान नेता

अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा भारत : रूसी प्रधानमंत्री पुतिन का बयान एजेंसी।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। वाल्ट्वाई पॉलिसी फोरम में संबोधन के दौरान पुतिन ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, जिससे भारत की संप्रभुता से समझौता हो।

पुतिन ने कहा कि अगर रूस से तेल खरीदने पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी, जिससे अमेरिकी



अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत अगर रूसी तेल की खरीद रोकता है, तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि भारत जैसे देश में जनता अपने नेतृत्व पर पैनी नजर रखती है और भारतीय लोग कभी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि उनका देश किसी भी ताकत के सामने झुके।

पुतिन ने यह भी जोड़ा कि अगर

रूसी तेल की आपूर्ति बंद होती है, तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें प्रति बैरल 100 डॉलर से भी ऊपर जा सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत के साथ रिश्तों को 'दोस्ताना' बताते हुए पुतिन ने कहा कि वे मोदी के साथ भरोसे के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने दिसंबर की शुरुआत में होने वाली अपनी भारत यात्रा को लेकर संतोष जताया और रूसी सरकार को

पुतिन ने ट्रंप को दी चेतावनी

रूसी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब इस साल के अंत में उनकी भारत यात्रा की संभावना जताई जा रही है। उनकी यात्रा से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भी भारत आने और शिखर सम्मेलन की तैयारियों के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है।

अमेरिकी टैरिफ पर प्रतिक्रिया - वल्ट्वाई डिस्कशन क्लब में अमेरिकी टैरिफ और भारत की ऊर्जा जरूरतों को लेकर पूछे गए सवाल पर पुतिन ने कहा कि यदि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देता है, तो उसे करीब 9 से 10 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि पीएम मोदी किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और भारत की गरिमा तथा रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेंगे। पुतिन ने कहा, यह पूरी तरह आर्थिक मामला है, राजनीतिक नहीं। अगर भारत हमारे ऊर्जा संसाधनों से पीछे हटता है, तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर प्रतिबंधों के बावजूद वह हमारे साथ व्यापार जारी रखता है, तो भी उसे चुनौती का सामना करना होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा।

निर्देश दिया कि व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

पुतिन ने सुझाव दिया कि भारत चाहे तो रूस से ज्यादा कृषि उत्पाद और दवाइयां आयात करके व्यापार संतुलन

को साध सकता है। अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए पुतिन ने कहा कि वाशिंगटन भारत जैसे देशों पर रूसी ऊर्जा न खरीदने का दबाव डालता है, जबकि खुद यूरेनियम के लिए रूस पर निर्भर रहता है।

कलेक्टर ने भोपालपटनम ब्लॉक में नव स्थापित सुरक्षा कैम्प चिल्लामरका का लिया जायजा

सुरक्षा कैम्प की स्थापना से नियद नेल्लानार योजना में शामिल गांवों में विकास कार्यों में आएगी तेजी

बीजापुर । बीजापुर जिले के कलेक्टर सबित मिश्रा ने भोपालपटनम ब्लॉक के सुदूर गांव चिल्लामरका में हाल ही में स्थापित सुरक्षा कैम्प का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे मे आवश्यक चर्चा की। चिल्लामरका में सुरक्षा कैम्प की स्थापना से नियद नेल्लानार योजना के तहत शामिल गांवों में विकास की रफ्तार तेज होगी और शासन की योजनाएं अब इन क्षेत्रों तक आसानी से पहुँच सकेंगी। इससे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की मुख्यधारा से वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्राथमिक शाला चिल्लामरका का औचक निरीक्षण किया और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को उल्लूख से चिल्लामरका तक सड़क निर्माण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना, काण्डलारपरती में विद्युतीकरण, मोबाइल



टावर के लिए सर्वे और ट्रैक्टर के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने चिल्लामरका में नवीन आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति भी प्रदान की, जिससे स्थानीय बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर एसडीएम वाय.के. नाग, एसडीओपी घनश्याम कामड़े, तहसीलदार लक्ष्मण राठिया, सीईओ संतोष देवांगन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बीजापुर के आदिवासी युवाओं को देशसेवा का मौका

जगदलपुर। बस्तर के आदिवासी युवा अब नक्सली वर्दी नहीं पहनेंगे, बल्कि वे अब सी वर्दी पहनेंगे, जिस पर उन्हें और पूरे समाज को गर्व होगा। ये युवा पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सकेंगे।

दरअसल बीजापुर जिले में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में आरक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यह भर्ती क्षेत्रीय युवाओं को सुरक्षा बलों में सेवा देने का अवसर प्रदान करेगी, साथ ही क्षेत्र की शांति एवं विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। आरक्षक के 126 पदों पर युवकों की और22 पदों पर युवतियों की भर्ती की जानी है। इसके लिए पंजीकरण एवं आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक निर्धारित है।पंजीकरण और आवेदन लेने की प्रक्रिया फुटबॉल स्टेडियम एजुकेशन सिटी, बीजापुर में पूरी की जाएगी।21 अक्टूबर से 6 नवंबर 2025 तक होगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष (01 अगस्त 2025 की स्थिति में) है। पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई 153 सेमी (छूट के बाद), सीना बिना फुलाए 74.5 सेमी और कम से कम 5 सेमी फुलाव आवश्यक है।महिला उम्मीदवार की ऊंचाई 40.5 सेमी (छूट के बाद) निर्धारित है। अधिक जानकारी हेतु मोबाइल नंबर- 62649-15190 पर संपर्क किया जा सकता है।

कबीरधाम पुलिस की मुस्तैदी से खप्पर यात्रा शांतिपूर्ण सम्पन्न

रिकॉर्ड भीड़ के बावजूद कानून-व्यवस्था पूरी तरह बनी रही

कबीरधाम । पैदल गश्त और सतत निगरानी से उपद्रवियों पर नियंत्रण। फ्लैग मार्च और सक्रिय पुलिस से आम जनता में भरोसा। लगभग 50 सदस्य और बदमाश थाने में बिठाए गए। वॉलेंटियर्स और एनसीसी/एनएसएस और स्काउट गाइड का महत्वपूर्ण सहयोग। मंदिर समितियों और संस्थानों ने पुलिस की प्रशंसा की। जनता का कहना ड़्क अब तक की सबसे बड़ी और सुरक्षित खप्पर यात्रा। पुलिस की सख्ती और समझाइश से शांति बनी रही। सम्प्त आयोजन के लिए जनमानस ने पुलिस का हृदय से आभार जताया। नवरात्र अष्टमी के अवसर पर पारंपरिक खप्पर यात्रा ऐतिहासिक, सफल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से

संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक श्री संजय ध्रुव, श्री अखिलेश कौशिक, श्री प्रतीक चतुर्वेदी, श्री भूपत सिंह धनेश्री, श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर, श्री आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में कबीरधाम पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की। इस वर्ष खप्पर यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी। कवर्धा के जनमानस का कहना है कि आज से पहले इतनी बड़ी भीड़ खप्पर यात्रा में कभी नहीं देखी गई थी। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की दृष्टि से यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, किंतु सभी व्यवस्थाएँ सख्ती और संवेदनशीलता के साथ लागू की गईं।

तांत्रिक अनुष्ठान भी होता है बस्तर दशहरा में

बुरी आत्माओं से बस्तर की सुरक्षा के लिए किया जाता है तांत्रिक अनुष्ठान

तांत्रिक अनुष्ठान में दी जाती है बकरों की बलि

जगदलपुर । विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा सिर्फ जन आकर्षण का ही केंद्र नहीं है, बल्कि इस दौरान पूरी की जाने वाली रस्में भी अलौकिक होती हैं। इन रस्मों में तांत्रिक पूजा अनुष्ठान भी शामिल है। यह अनुष्ठान बस्तर को बुरी आत्माओं के कहर से बचाने और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान बकरों की बलि भी दी जाती है। यह रस्म निशा जात्रा के दौरान पूरी की जाती है। रहस्यों और रोमांच से भरे बस्तर दशहरा वस्तुतः देवी आराधना का महापर्व है। यह महापर्व बस्तर संभाग की प्रथम पूजनीया माई दंतेश्वरी को समर्पित है। इस महापर्व में बस्तर के सभी देवी देवताओं का आगमन होता है। उनके रहवास की अलग अलग



व्यवस्था रहती है। नियमित पूजा अर्चना का दौर चलते रहता है। इस दौरान तरह तरह की प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों का नियमानुसार पालन भी किया जाता है। इन्हीं रिवाजों में शामिल है तांत्रिक पूजा अनुष्ठान। तांत्रिक पूजा अनुष्ठान निशा जात्रा के दौरान पूरा किया जाता है।यह रस्म बस्तर राजवंश के लोगों द्वारा ही पूरा कराने की परंपरा है। बीती रात निशा जात्रा और तांत्रिक पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ।देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बस्तर राजवंश के कुलदीपक राजा कमलचंद भंजदेव ने देर रात निशा जात्रा की रस्म

पूरी की। इस दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाने के साथ बकरों की बलि भी दी गई। बस्तर दशहरा की इस अनूठी रस्म के जरिए बस्तर को बुरी प्रेत आत्माओं से बचाने की प्रार्थना की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि के बीच देर रात को यह रस्म निभाने की परंपरा 600 साल चली आ रही है। इस रस्म के तहत देर रात राजा कमलचंद भंजदेव के साथ बस्तर अनुष्ठान का आयोजन हुआ।देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बस्तर राजवंश के कुलदीपक राजा कमलचंद पैदल चलकर अनुपमा चौक स्थित गुड़ी मंदिर पहुंचे।

सूने मकान में चोरी करने वाले नाबालिग आरोपी सहित 2 गिरफ्तार

रायपुर । थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत सेक्टर 01 स्थित प्रार्थी के सूने मकान को बनाये थे अपना निशाना। घटना में संलिप्त है विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक। दोनों के कब्जे से चोरी की सोने व चांदी के जेवरात, बिस्किट व सिक्के, मूर्ति तथा नगदी रकम किया गया है जप्त। घटना में प्रयुक्त एवेंजर मोटर सायकल को भी किया गया है जप्त। जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 12,50,000/- रुपये। आरोपी देवा महानंद उर्फ देवू पूर्व में भी हत्या के प्रकरण में थाना पंडरी से रह चुका है जेल निरुद्ध। आरोपी/अपचारी के विरुद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 190/25 धारा 331(ए), 305(ए) बी.एन.एस. का अपराध किया है पंजीबद्ध। एण्टी फ्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। विवरण - प्रार्थी हरीश मोटवानी निवासी सेक्टर 01 एच.आई.जी. देवेन्द्र नगर रायपुर ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 18.09.2025 को वह अपने घर में ताला लगाकर सपरिवार नागपुर महाराष्ट्र गया था, कि प्रार्थी दिनांक 22.09.2025 को रात्रि वापस रायपुर आकर अपने घर के मेन दरवाजे के लॉक को खोलकर अंदर प्रवेश कर देखा तो कमरों में रखा सामान बिखरा हुआ था एवं आलमारियों व लॉकर का लॉक टूटा हुआ था। लॉकर में रखा सोने व चांदी की बिस्किट व जेवरात, सिक्के, चांदी का मूर्ति व नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर कमरों में रखे आलमारियों का ताला व लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने व चांदी के जेवरात, सिक्के, मूर्ति व नगदी रकम को चोरी कर ले गया था, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 190/25 धारा 331(ए), 305(ए) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

शीतला शक्ति पीठ में ज्योत ज्वारा का विसर्जन हुआ, शोभायात्रा मे देव विग्रह झूमते रहे

नगरी। शीतला शक्ति पीठ सिहावा में शारदीय नवरात्रि में ज्योत ज्वारा विसर्जन परम्परानुसार किया गया।इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ रही।महा नवमी की प्रातः सरोवर स्नान के लिये शोभा यात्रा प्रारंभ हुआ जो शीतला तालाब में ,पहुँच कर ज्वारा विसर्जित की गई। ऋषि पंचमी सेवा मण्डली गणेश घाट सिहावा द्वारा गाये जा रहे माता सेवा के साथ गढ़ की देवी देवताये अपने पूरे स्वरूप में डांग ,बाना आदि लिये हुए विसर्जन शोभायात्रा में झूमते रहे।माता तालाब में विधि विधान से विसर्जन उपरांत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किये गए।नवमी के अवसर पर माता का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना किया गया ।फिर माता को भोग लगाकर भण्डारा प्रारम्भ की गई।भण्डारा गोल्डी चोपड़ा व परिवार बेलरागांव द्वारा की गई।समिति के अध्यक्ष कैलाश पवार ने शारदीय नवरात्रि पर्व पर मिले सहयोग के लिये सभी का आभार माना।प्रमुख संचालक कलम सिंह पवार, महासचिव नेम सिंह बिशेन,सह सचिव नरेंद्र नाग,नारद निषाद,बुधेश्वर साहू,कोशाध्यक्ष गेंद लाल यादव, तुकाराम साहू, पुजारी ज्ञान सागर पटेल,तुका सिंह बेश,बलदेव

निषाद,राजकुमार निषाद,दीपक तंवर,छबि ठाकुर, संजय सारथी,रामलाल नेताम,प्रवीण गुप्ता,रंगन नाहटा,भरत नेतमलकर,महेन्द्र कौशल,कुँवर साहू,मंशा राम गौर,जगमू साहू,नरेश पटेल ,महेश साहू,लाल जी साहू,संतोष पवार,ललित निर्मलकर,सुभाष यादव,महेन्द्र साहू ,अभय नेताम , खिरभान शाण्डिल्य,नवल साहू,दिनेश पटेल,बैजनाथ पटेल,बाल सिंह शोरी,मंशा गौर,तुलसी कुंजाम,सुंदरियां साहू,चरणबति नेताम,मेहतर गौर, बुध्दू सोम, सुमेरू शांडिल्य,पुरन बिसेन, राम प्रसाद नेताम, कमलेश निषाद, हेमलाल ध्रुव, चंद्रभान निषाद, रोहित साहू, बिष्णु साहू, चैन सिंह मरकाम, शंकर पटेल,चंदन देवांगन, शशिकला शांडिल्य,देवन्तीन श्रीमाली,रीना बिसेन,परमीला साहू,नंदबाई पटेल खेमिन यादव,गायत्री पटेल,गोमती निषाद,नोहर साहू,अभिलाषा शाण्डिल्य, बिन्दा मरकाम आदि की भूमिका रही। एकादशी पर होगा सहस्त्रबाहु रावण का वध सिहावा गढ़ के छिपली पारा में दशहरा अनोखी परम्परा से मनाया जाता है।यहाँ रावण का नहीं अर्पितु सहस्त्रबाहु रावण का वध होता है।मिट्टी का नग्न पुतला बनाया जाता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा हुई पूरी : कोतबा लवाकेरा मार्ग में कोकिया नाला पर बनेगा उच्चस्तरीय पुल

4 करोड़ 14 लाख रुपए की मिली मंजूरी, सकरा एवं जर्जर पुल से मिलेगी राहगीरों को निजात

जशपुरनगर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घोषणा अनुरूप जिलेवासियों के लिए विकास का नया द्वार खुल गया है। जिले के कोतबा लावकेरा मार्ग पर कोकिया नाला में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए शासन से 4 करोड़ 14 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।क्षेत्र वासियों की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सराईटोली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी। सीएम साय ने घोषणा पूरी करते हुए कोकिया नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मंजूरी दी है।यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को झारखंड और ओडिशा राज्यों से जोड़ता है।वर्तमान में जर्जर और सकरे पुल के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी होती थी,



खासकर बरसात के दिनों में जब नाला उफ़ान पर होता था और आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता था, साथ ही दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती थी।

नए पुल के निर्माण से न केवल ग्रामीणों को राहत मिलेगी, बल्कि तीन राज्यों के बीच संपर्क और और भी अधिक मजबूत होगा। व्यापार, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह मार्ग वरदान साबित होगा। आपातकालीन सेवाएं जैसे एंबुलेंस और अग्निशमन वाहन भी अब सुगमता से गुजर पाएंगे।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का क्षेत्र वासियों ने जताया आभार

कोतबा लवाकेरा मार्ग कोकिया नाला में उच्च स्तरीय पुल कि मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्र वासियों की यह बड़ी मांग थी,साथ ही यह सौगात जशपुर जिले के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

कोरिया। देवगढ़ रेंज क्षेत्र में फर्जी वन अधिकार पट्टा मामले ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों को

नकली पट्टा थमाकर न केवल आर्थिक रूप से ठगा गया, बल्कि उनके साथ खुला छल भी किया गया है। जब इन पट्टों को ग्रामीणों ने वन विभाग में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया, तो अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये दस्तावेज पूरी तरह से नकली और फर्जी हैं।

कोरिया वनमण्डल के डीएफओ चन्द्रशेखर शंकर सिंह परदेशी ने जानकारी देते हुए बताया कि वन अधिकार पट्टा केवल जिला स्तर पर विशेष समिति की बैठक के बाद ही जारी होता है, जिसमें कलेक्टर, डीएफओ और अन्य संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। उनके बिना कोई भी पट्टा मान्य नहीं होता। यदि किसी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों से



पैसे वसूलें हैं, तो यह एक गंभीर कानूनी अपराध है। डीएफओ परदेशी ने सख्त लहजे में कहा कि यदि इस फर्जीवाड़े में वन विभाग का कोई कर्मचारी भी संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चार से पांच अन्य ग्रामीणों को भी इसी तरह के फर्जी पट्टे दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक संगठित धोखाधड़ी का मामला है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद

देवगढ़ रेंज क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों में जहां एक ओर आक्रोश व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर वे अब सतर्क भी हो गए हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें जल्द काफ़ी पैसा वापस दिलाया जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

अहाता लाइसेंस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को मिलेगी आधुनिक सुविधाएँ

आबकारी विभाग ने लॉन्च किए मनपसंद और सेवा सुविधा मोबाइल एप

रायपुर। आबकारी विभाग द्वारा जिले में शराब दुकानों के संचालन को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सचिव आबकारी विभाग आर. संगीता एवं कलेक्टर सुकुमा देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में जिले में संचालित चार मदिरा दुकानों में अहाता लाइसेंस हेतु पहले आओ पहले पाओ के अंतर्गत निविदा जारी किया गया है। अहाता व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को अल्पाहार व सैक्स, एयरकूल्ड और ए.सी. सुविधा, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण तथा मनोरंजन के लिए मधुर संगीत जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। वहीं गाना-बजाना, नृत्य करना, शोरगुल करना, उच्छृंखल व्यवहार एवं सिंगल-यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकान संचालकों को आवश्यक अनुमतियाँ जैसे एफएस.एस.ए आई. लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करते पकड़े जाने पर



पहली बार 1,000 से 5,000 रुपये और पुनः अपराध करने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी गजेन्द्र नेताम ने जानकारी दी कि राज्य शासन ने दो मोबाइल एप लॉन्च किए हैं। सेवा सुविधा एप के माध्यम से प्लेसमेंट कर्मचारियों को पारिश्रमिक, ड्यूटी, संचार सूचना और शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं, मनपसंद एप के जरिए उपभोक्ता शराब

दुकानों में उपलब्ध ब्रांड, स्टॉक और विक्रय दर की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें देशी और विदेशी मदिरा की बोटल, अड्डा और पाव की दर सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी।श्वस् ड्रिंइड्रसइंट्रू ड्रिंस् स्ह्क के माध्यम से दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को उपस्थिति और वेतन संबंधी रिपोर्ट को और अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाया गया है।ज्ञभद्यद्यदहदह ड्रदड़्,श्वश्द्यदह्दह्दह्दभट्टु के माध्यम से शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज

कराने एवम शिकायत के निराकरण को भी डिजिटलाइज किया गया है। शराब दुकानों से संबंधित शिकायत या अवैध शराब की जानकारी देने के लिए टोल-फ्री नंबर 14405 तथा मोबाइल नंबर 9424102102 जारी किए गए हैं। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने टोलफ्र बैठक में अधिकारियों को इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मां अंगारमोती की महिमा का बखान किया पं. धीरेंद्र शास्त्री जी ने

वायरल वीडियो में सुनाया चमत्कार 7 4 अक्टूबर से रायपुर में होगी हनुमंत कथा

रायपुर । बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं। 4 अक्टूबर से राजधानी रायपुर के गुडियारी क्षेत्र में होने जा रही हनुमंत कथा से पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां अंगारमोती के चमत्कारों का उल्लेख करते नजर आ रहे हैं।वीडियो में पं. शास्त्री बताते हैं कि जब वे लगभग 15 वर्ष के थे, तब एक बार धमतरी जिले के गंगरेल बांध के पास स्थित मां अंगारमोती के दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन के बाद उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई, लेकिन सभी दुकानें बंद थीं। इस बीच उन्हें एक वृद्धा दिखाई दी, जिसने पहले उन्हें चना दिया और फिर चाय की इच्छा जाहिर करने पर तुरंत गर्म चाय लाकर दी। शास्त्री ने कहा, ऐसी स्वादिल चाय मैंने जीवन में पहले कभी नहीं पी थी।



लोकेंन जब व बाद में कई बार मां अंगारमोती के दर्शन करने गए, तो वह वृद्धा फिर कभी नहीं दिखीं। शास्त्री इसे एक दिव्य चमत्कार मानते हैं और इसे मां की कृपा का प्रमाण बताते हैं। मां अंगारमोती की दिव्यता और मान्यता धमतरी जिले में स्थित गंगरेल डैम की सुरम्य वादियों के बीच विराजमान हैं मां अंगारमोती, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं, देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र हैं। इन्हें 52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। कहा जाता है कि यहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।

14 आईएसएस अधिकारियों का तबादला

रायपुर। राज्य शासन द्वारा 14 आईएसएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार रेणु जी पिछ्हे को व्यापम अध्यक्ष तो सुब्रत साहू को छ.ग. प्रशासन अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है वहीं सोणमणि बोरा को प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

जारी आदेश के अनुसार रेणु जी पिछ्हे अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अति. प्रभार अध्यक्ष, व्यापम, अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अध्यक्ष, व्यापम, के पद पर पदस्थ करते हुए अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग महानिदेशक, छा प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग को को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त

महानिदेशक, छा प्रशासन अकादमी के पद पर पदस्थ करते हुए दिनांक 01.10.2025 से टोपेश्वर वर्मा, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर के सेवानिवृत्ति के उपरांत अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

डॉ रोहित यादव,सचिव, ऊर्जा विभाग तथा अति. प्रभार अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को सचिव, जनसंपर्क विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिव, पर्यटन एवं

संस्कृति विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) तथा अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही डॉ रोहित यादव, भा.प्र.से. के सचिव, जनसंपर्क विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर पी. दयानंद, सचिव, मुख्यमंत्री तथा अति. प्रभार सचिव, खनिज साधन विभाग एवं सचिव, जनसंपर्क विभाग को केवल सचिव, जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

अविनाश चम्पावत, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, जन शिक्षायत निवारण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मुकेश कुमार बंसल, सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, वाणिज्यिक कर (आब. एवं पंजी. को छोड़कर) विभाग

मुकेश कुमार बंसल, भा.प्र.से.. के सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, वाणिज्यिक कर (आब. एवं पंजी. को छोड़कर) विभाग, सचिव,मुख्यमंत्री को सचिव, विमानन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर बसवराजू एस., भा.प्र.से. (2006), सचिव, मुख्यमंत्री तथा अति. प्रभार सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सचिव, विमानन विभाग को केवल सचिव, विमानन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

अंकित आनंद, सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग को सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव, वाणिज्यिक कर

(पंजीयन) विभाग तथा अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अंकित आनंद, भा.प्र.से. के सचिव, इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (1997), प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान केवल प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

भुवनेश यादव, सचिव, समाज कल्याण विभाग तथा अति. प्रभार आयुक्त, नि.शक्तजन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कुलदीप शर्मा, रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वेंयर हाऊसिंग कांर्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

रवि मित्तल, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा अति. प्रभार आयुक्त, जनसंपर्क मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवाद को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

डॉ. परिहा आलम,संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अति. प्रभार संयुक्त सचिव, श्रम विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, खाद्य के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

जितेंद्र यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला राजनांदगांव के पद पर पदस्थ किया गया है।

नेताप्रतिपक्ष एवं जी नफ रत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते है ठीक भाजपा उल्टे धर्म संप्रदाय की बात कर नफत फैलाने की बात करते है विचार धारा संविधान की विपरीत है राहुल गांधी संविधान के संरक्षण की बात करते है ,जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर अध्यक्ष उधोराम वर्मा ने जारी विज्ञप्ति में कहा है चेतावनी देते हुए तत्काल गिरफ्तारी कर संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्यवाही की माग की है,आज विधान सभा थाना में लिखित शिकायत कर हत्या का मामला दर्ज करने की माग किए है थाना विधानसभा में लिखित आवेदन देने वालों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष उधोराम वर्मा,पूर्व सांसद छाया वर्मा,मोहन लाल वर्मा, घनश्याम वर्मा, लोकेश साहू, अंकित वर्मा युवा अध्यक्ष,मनहरन वर्मा, मनसा,अरुण शुक्ला, वीर देवागन राजू यादव भिखू प्रशांत कुरें भागवत लहरी संतोष पाल गावेस साहू,राजू सरपंच खौली,गगन वर्मा, सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में बढ़ रही है सौर ऊर्जा की पहुंच

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में बढ़ रही है सौर ऊर्जा की पहुंच

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से मिल रही नई रौशनी

रायपुर। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले में घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। को 1 किलोवाॉट सिस्टम पर २45,000, 2 किलोवाॉट सिस्टम पर २90,000 और 3 किलोवाॉट अथवा उससे अधिक क्षमता पर २1,08,000 तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। इस योजना का फायदा उठाकर उपभोक्ता अपने बिजली खर्च में बड़ी बचत कर रहे हैं। खैरागढ़ शहर के गोलबाजार निवासी श्री प्रेमचंद जैन ने अपने घर में 9 किलोवाॉट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है। उनका कहना है कि सोलर ऊर्जा से उनके बिजली बिल में लगभग



80 प्रतिशत की कमी आई है और अब मासिक बिल केवल २800 के करीब रह गया है। सेवा पर्व के अवसर पर जिले के विभिन्न ग्रामों डामरी, अतरिया, कुम्हि, आमगांव, अमलीडीहकला, साल्हेवारा, खमतराई, लिमो, खम्हारडीह, मुझीपार, कामठा समेत अन्य गांवों में सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गई तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना न केवल आमजन को बिजली बिल से राहत दे रही है, बल्कि जिले को स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार और आर्थिक बचत की दिशा में भी सशक्त बना रही है।

सुकमा । पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देश पर आगामी 2 अक्टूबर 2025 को जिले की सभी ग्राम पंचायतों और आश्रित ग्रामों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम सभाओं में पंचायतों की आय-व्यय समीक्षा, मनरेगा कार्यों की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अंकेक्षण, खाद्यान्न वितरण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, कर निर्धारण एवं वसूली प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।

इसके साथ ही, पंचायत उन्नति सूचकांक (च०ए०) के परिणाम साझा किए जाएंगे तथा ग्रामीणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय प्रदर्शन डेटा भी प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभाओं में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उत्पाजन हेतु



एग्रीस्टेक पोर्टल एवं इंटीग्रेटेड फ़ार्मर पोर्टल में पंजीयन, डिजिटल क्राॅप सर्वे और गिरदावरी की जानकारी ग्रामवार वाचन कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, राष्ट्रीय पोषण माह 2025, तथा भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय

सहकारिता वर्ष 2026 से जुड़ी गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। ग्राम सभाओं की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे ठे छम्छाल्ट मोबाइल ऐप में अपलोड किया जाएगा तथा विकरण वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल और जीपीडीपी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।

जिला सीईओ श्री मुकुन्द ठाकुर ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम सभा से संबंधित सभी अधिकारी-कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ग्राम सभाओं का सफ ल आयोजन सुनिश्चित करें।

राज्य स्तरीय वृद्धजन दिवस पर मुख्यमंत्री ने की अहम घोषणाएं

रायपुर। सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सियान गुड़ी नाम से एक नई पहल शुरू करने जा रही है। यह विशेष केंद्र उन बुजुर्गों के लिए होंगे, जिन्हें अपने घर में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पातीं। इन केंद्रों में उन्हें रहने, खाने और स्वास्थ्य जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

जिले में औद्योगिकरण की नई लहर दिख रही

धमतरी । छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला अपनी भौगोलिक स्थिति, कृषि संपन्नता और संसाधनों की प्रचुरता के कारण औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। राजधानी रायपुर और औद्योगिक नगरी दुर्ग-भिलाई के निकट होने से यह जिला निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हो रहा है। शासन और प्रशासन के ठोस प्रयासों के चलते जिले में औद्योगिकीकरण की नई लहर दिखाई दे रही है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं बल्कि जिले की आर्थिक प्रगति को भी नई गति मिल रही है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा धमतरी जिले के करेली बड़ी और

भालूझुलन में फूड पार्क का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। यह फूड पार्क कृषि आधारित उद्योगों को नई दिशा प्रदान करेगा तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त करेली बड़ी, भालूझुलन और जामगांव में औद्योगिक क्लस्टरों का विकास किया गया है। ये स्थल रायपुर से अत्यंत निकट होने के कारण निवेशकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं।

धमतरी जिले में पाँच औद्योगिक क्लस्टरों की योजना है। इनमें से तीन क्लस्टरों का लोकार्पण हो चुका है तथा शेष का भूमिपूजन शीघ्र ही किया जाएगा। इन क्लस्टरों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (स्वस्व्) को मजबूती मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होगा।

धान की प्रचुर उपज के कारण धमतरी को धान का कटोरा कहा जाता है। जिले में धान से संबंधित उद्योगों जैसे राइस मिल, चावल आधारित प्रसंस्कृत उत्पाद, पैकेजिंग इकाइयाँ और बाय-प्रोडक्ट उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं। इसी दृष्टि से शासन द्वारा छत्ती और कचना में मेगा फूड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विशेष रूप से छत्ती क्षेत्र का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसके स्वीकृत होने पर जिले की औद्योगिक संरचना और अधिक सुदृढ़ होगी।

इन मेगा फूड पार्कों में धान, सब्जी, दलहन और अन्य कृषि उत्पादों का वैज्ञानिक एवं आधुनिक तकनीक से प्रसंस्करण किया जाएगा। तैयार उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने की योजना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और जिले की आर्थिक स्थिति और मजबूत बनेगी।

जिले में औद्योगिकीकरण को गति देने में प्रशासन की भूमिका उल्लेखनीय है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा स्वयं औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रख रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है तथा निवेशकों को आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे हों। वर्तमान में मेगा फूड पार्क बगौद (तहसील कुरूद) में औद्योगिक भूमि का आबंटन किया जा रहा है। यहाँ अब तक 13 उद्योग उत्पादन में आ चुके हैं, जिनमें 63.84 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 236 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा 25 उद्योग निर्माणाधीन हैं, जिनमें 116.59 करोड़ रुपये का निवेश एवं 446 रोजगार प्रस्तावित हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम

करेलीबड़ी (तहसील मगरलोड) और ग्राम भालूझुलन (तहसील कुरूद) में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु क्रमशः 14.00 हेक्टेयर एवं 11.00 हेक्टेयर भूमि पर कुल 19.38 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इसी प्रकार ग्राम जामगांव (तहसील कुरूद) में 10.00 हेक्टेयर भूमि पर 6.43 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण पूरा किया गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम छत्ती (तहसील धमतरी) एवं ग्राम कचना (तहसील भखारा) में क्रमशः 18.21 हेक्टेयर एवं 8.42 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक लेण्ड बैंक हेतु हस्तांतरित की गई है। छत्ती क्षेत्र एनएच-30 से लगा हुआ है तथा कचना धमतरी-रायपुर मार्ग पर रायपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

कलेक्टर एवं एसएसपी ने बार/क्लब संचालकों की ली बैठक, कहा किसी भी हाल में रात 12 बजे तक पूर्ण रूप से हो बंद, अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई

बिना पूर्व सूचना-अनुमति के किसी भी प्रकार के आयोजन न हों

कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने पर करें सहयोग, बिगड़ने पर होगी कार्रवाई

रायपुर । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह ने राजधानी के बार संचालकों और आबकारी अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी स्थिति में बार एवं क्लब के खुलने और बंद होने के समय का कड़ाई से पालन करें। निर्धारित समय रात्रि 11:30 बजे उपभोक्ताओं का प्रवेश और सर्विस पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और रात के 12 बजे बार और क्लब अनिवार्य रूप से बंद हो जाने चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी डॉ सिंह ने कहा कि अब निर्धारित समय पर बार एवं क्लब बंद न होने की स्थिति में पुलिस कार्रवाई करेगी।

कलेक्टर ने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने या बिगड़ने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बार/क्लब जिम्मेदार हैं। सभी संचालक कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का



सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व अनुमति एवं सूचना के बार/क्लबों में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, पार्टी, कॉन्ग्रेस या मनोरंजन आयोजन न किया जाए। इसके लिए कलेक्टर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त कर एकदिवसीय अनुज्ञप्ति (एफएल.-5 व एफएल.-5(क)) लेना अनिवार्य है। प्रचार प्रसार करने के पक्षत अनुमति लेने का प्रक्रिया प्रारंभ करने पर कार्रवाई की जाएगी और अनुमति भी प्रदान नहीं की जाएगी। कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि 21 वर्ष

से कम आयु के व्यक्तियों को बार में प्रवेश या मदिरा विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसका अनिवार्यतः पालन किया जाए। सभी बार एवं क्लब अपने प्रवेश द्वार पर संचालन समय, ग्राहकों की वैध आयु, नशीली दवाओं के विरुद्ध चेतावनी, सूचना एवं शिकायत हेतु पुलिस व आबकारी विभाग का संपर्क नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि बार/क्लब में केवल वैध रूप से प्राप्त ड्यूटी पेड मदिरा का ही विक्रय किया जाए। अन्य प्रांत की या नॉन-ड्यूटी

पेड मदिरा का विक्रय पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि मदक पदार्थों के विज्ञापन, प्रलोभन, स्क्रीम या अश्लील प्रचार-प्रसार पर पूर्णतः रोक रहेगी। बार/क्लब में कार्यरत व्यक्तियों की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही की जाए और उनकी सूची आबकारी एवं पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जाए। मदिरा का विक्रय केवल अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग हेतु ही किया जाए। पार्सल विक्रय करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित नियमों का पालन न करने वाले बार एवं क्लब संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संचालकों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि जिले में कानून-व्यवस्था और सामाजिक वातावरण सुव्यवस्थित बना रहे। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि आबकारी अमला अपने संबंधित क्षेत्रों पर कड़ाई के साथ नजर रखें और पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निरंतर व्यवस्था बनाए रखें।

रेल संरक्षा को मिलेगी मजबूती : बिलासपुर मंडल के 15 स्टेशनों पर लगेगी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग

रायपुर। भारतीय रेलवे ने संरक्षित रेल परिचालन को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत बिलासपुर रेल मंडल के 15 शेष पैनल इंटरलॉकिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी.

इस आधुनिक प्रणाली को स्थापित करने में अनुमानित तौर पर 298.60 करोड़ रुपये की लागत आएगी. जिन 15 स्टेशनों को इस परियोजना में शामिल किया गया है, उनमें बिश्रामपुर, कमलपुरग्राम, अंबिकापुर, मौहारी, हरद, पाराडोल, कोतमा, बिजुरी, करंजी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, घुटजू, कलमीटार, लैंको और कुसमुंडा शामिल हैं. यह स्वीकृति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली भारतीय रेल की स्वदेशी ट्रेन

सुरक्षा प्रणाली 'कवच' के सफल क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग न केवल ट्रेन परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाएगी, बल्कि यह कवच प्रणाली के साथ सीधे एकीकृत होकर वास्तविक समय (रियल टाइम) में डेटा साझा करने में सक्षम होगी. रेलवे बोर्ड की इस स्वीकृति के बाद, इन 15 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और कवच प्रणाली का संयुक्त संचालन रेलवे संरक्षा मानकों को और मजबूत करेगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित एवं निर्बाध रेल यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी.

इस परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभ-ट्रेन संचालन की संरक्षा और दक्षता में वृद्धि.कवच प्रणाली के साथ सरल और सहज एकीकरण. तेज ट्रेन नियंत्रण और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया.

संपादकीय

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग सदैव रहेगा

कश्मीर को भारत-पाकिस्तान के बीच का मामला बताते हुए अमेरिका द्वारा दोनों मुल्कों के दरम्यान कोई दबाई न करने का इशदा जताया गया। अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रेस वार्ता में इस मुद्दे को भारत-पाकिस्तान पर छोड़ने की बात की। यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें भारत-पाक के बीच युद्धविग्रम कराने में ट्रंप की भूमिका का दावा किया गया था। हालांकि भारत सरकार ने बार-बार जोर दिया कि सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दे



मानव देवत्व को पाए।

नील गगन की चुप्पी गहरी, मन की पीड़ा मोती ठहरी। अश्रु बने जब दीपक प्यारे, जीवन के उजियारे सारे।

मौन धरा से स्वर उठता है, दुःख में भी विश्वास मिलता है। करुणा का सागर साथ रहेगा, हर आँसू में विश्वास जागेगा।

वेदना गाती गीता प्यारी, पीड़ा देती राह हमारी

अंधकार में ज्योति दिखाए, मानव देवत्व को पाए।

धरती बोले, नभ दोहराए, संसार यह गीत सुनाए। क्षणभंगुर तन, अमर है प्राण जीवन का संदेश महान।

आज गगन में दीप जला लोक में पिर आलोक सजा क्यों देते हम अधियारे को दोष तमस में प्रकाश-आलोक सजा।

– संजीव ठाकुर



PM : 2024 -
Vishwa Sarkar Ka Vikalp

QR CODE SCAN

कर प्रेमन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन



Modimaya
Vaidik_Netritva



Rashtriya Ekta



DLF-Vadra-
Bhrasht Tantra



Silent Assassins
Jan11,1966



Accursed & Jihadi
Neighbour

अकल्पनीय हिंसा, उथल-पुथल गले नहीं उतरता

अवधेश कुमार

नेपाल में उथल-पुथल के बीच सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंतु इसके पूर्व तीन दिनों में नेपाल जिस अकल्पनीय हिंसा, उथल-पुथल और हृदयविदारक घटनाओं से गुजरा उनने सबको डराया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरुद्ध जेन जी के बैनर से जारी विरोध प्रदर्शन कितने उग्र, हिंसक, अराजक और अनेक मायनों में अपराधिक भी हुए। लगता था जैसे उग्र भीड़ नेपाल की राजनीति और सत्ता से संबंधित हर चीज नष्ट करना चाहती हो। संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास और उच्चतम न्यायालय जला देना, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, नेताओं को उनके घरों में घुस कर, सड़कों पर दौड़ा कर पीटना और महिलाओं को भी नहीं बख्शाना किसी आंदोलन का पर्याय नहीं हो सकता। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी को जलाया गया। शेर बहादुर देउबा की पत्नी विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा की पिटाई वाकई हृदयविदारक थी। लगता था जैसे भीड़ किसी भी नेता को नेपाल की धरती पर साक्षात सहन करने को ही तैयार नहीं थी। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण ऐसा हिंसक विरोध गले नहीं उतरता।

जरा सोचिए, 28 अगस्त को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स को प्रतिबंधित किया था, जिन्होंने वहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और 3 सितम्बर को आंदोलन आरंभ हो गया। ठीक है कि सोशल मीडिया नई पीढ़ी और सक्रिय लोगों के जीवन में इतनी पैठ बना चुका है कि प्रतिबंध सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं हो सकता। नेपाल में सोशल मीडिया के माध्यम से 12 अरब डॉलर माह से ज्यादा का कारोबार हो रहा है। नई पीढ़ी रील बनाने से लेकर अन्य वीडियो आदि से भारी कमाई कर रही है। सोशल मीडिया भुगतान का भी जरिया बन गया है। सरकार का कहना था कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया जा रहा था, सांप्रदायिक घृणा भी फैलाई जा रही थी।

इसलिए इनका नियमन जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने निबंधन की बात कही थी कि जिसे आधार बना कर सरकार ने प्रतिबंध ही लगा दिया था। उग्र विरोध को देखते हुए प्रतिबंध हटा लिया गया। केवल प्रतिबंध विरोध का कारण होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। यह तो नहीं कह सकते कि नेपाल में असंतोष और विरोध के कारण नहीं है। 2006 में माओवादियों के शांति समझौते के बाद 2008 में राजशाही के अंत के साथ शुरू संसदीय लोकतंत्र का प्रयोग नेपाल में अनेक विद्वरूपताओं का शिकार हुआ। 17 वर्षों में 14 सरकारों के आने-जाने से बड़ा प्रमाण राजनीतिक अस्थिरता का क्या हो सकता है। ओली ने भारत विरोधी चीन के प्रति झुकाव रखने वाले अजीब किस्म के नेपाली राष्ट्रवाद को प्रचलित किया जिनसे उनके समर्थक-विरोधी, दोनों पैदा हुए।

आप देखेंगे कि काफी समय से नेपाल में अलग-अलग किस्म के आंदोलन चलते रहे हैं, जिनमें नेपाल को फिर हिन्दू राष्ट्र घोषित करने तथा राजशाही की पूर्ण वापसी प्रमुख था। इनकी रैलियों में हजारों लोग आने लगे। ओली ने राजा



ज्ञानेंद्र की गतिविधियों को रोकने की कोशिश की तथा आंदोलन में तोड़फोड़ के लिए उन पर 7 करोड़ 93 लाख का जुर्माना भी लगाया। उनकी सुरक्षा परिवर्तित कर दी गई। हाल में नेपाल में मुस्लिम तथा ईसाई समुदाय की बढ़ती आबादी के विरुद्ध भी असंतोष बढ़ा है। मुस्लिम आबादी तराई या मधेस क्षेत्र में है, और उसके कारण समाज में असहज स्थिति पैदा हुई है। इसके विरुद्ध भी छोटे-बड़े प्रदर्शन चलते रहे हैं।

नेपाल वि का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र था। 2008 की संविधान सभा सह संसद ने बिना घोषणा के हिन्दू राष्ट्र का अंत कर नेपाल को सेक्युलर देश घोषित किया। इसमें बालेंद्र शाह जैसे रैपर तथा सुदुन गुरुंग जैसे एनजीओ संचालकों ने नई पीढ़ी को आकर्षित किया। बालेंद्र ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट, दोनों को पराजित कर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता तथा 2023 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें वि के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल कर दिया। यह नेपाल के लोगों खासकर युवाओं की बदलती प्रवृत्ति का प्रमाण था कि स्थापित नेताओं की जगह ऐसे लोगों को प्रमुखता मिली।

बेरोजगारी के कारण युवाओं का विदेश पलायन नेपाल के लिए आम बात थी। आज नेपाल के लोग दुनिया के अनेक कोनों में हैं, और वहां से प्रभावित हैं। राजनीति, सत्ता, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, विदेश संबंध, नेताओं की स्थिति पर गहन विमर्श करते हैं तो वहां असंतोष और विद्रोह के आधार व्यापक थे एवं लोगों में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से उभर कर नई व्यवस्था स्थापित करने का भाव होना स्वाभाविक है। किंतु कई बार हम जल्दबाजी में घटनाओं की पृष्ठभूमि, उसके पीछे की सोच तथा इसके भयावह प्रभावों का आकलन नहीं कर पाते और अराजक

(संपादकीय + संदेश)

स्वदेशी एवं स्वावलम्बन ही नये भारत का आधार



ललित गार्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना महोत्सव यानी प्रत्येक वर्ष विजयदशमी के अवसर पर संघ प्रमुख का उद्घोहन एक नए संदेश और नये दृष्टिकोण के साथ सामने आता है, इस उद्घोहन का पूरा राष्ट्र इंतजार करता है। इस बार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई ऐसी बातें कहीं, जो सरकार के साथ समाज के लोगों का ध्यान खींचने वाली हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर थोपे गए टैरिफ की चर्चा की। 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ ने भारत के समक्ष जो कठिन चुनौती खड़ी कर दी है, उसका प्रभावी ढंग से सामना स्वदेशी और स्वावलंबन की राह पर चलकर ही किया जा सकता है। भागवत ने संबोधन में स्वदेशी और स्वावलंबन को नए भारत का आधार बताया है। उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में परस्पर निर्भरता एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन यह निर्भरता कभी भी बंधन या मजबूरी में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा ताकि विदेशी निर्णयों और नीतियों पर हमारी नियंत्रण क्षमता सीमित न हो जाए। उनका कहना था कि स्वदेशी का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी शक्तों पर और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संबंध बनाएं।

संघ की स्थापना का यह अवसर केवल एक उत्सव मात्र नहीं था, बल्कि यह आयोजन भारत की आत्मा और उसके भविष्य की एक गहन घोषणा थी। भागवत ने स्पष्टता और गंभीरता से अपने विचार रखे, भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक नया क्षितिज भी उद्घाटित किया। यह आयोजन संघ के सौ वर्ष सम्पूर्णता की साधना का मूल्यांकन ही नहीं, बल्कि आने वाले सौ वर्षों की दिशा का भी उद्घोष था। नई इबारत लिखते हुए भागवत ने स्पष्ट कहा कि संघ की कार्यप्रणाली का सार है, नए मनुष्य एवं सशक्त-स्वावलम्बी भारत का निर्माण। यह विचार सुनने में सरल लग सकता है, किंतु इसके निहितार्थ अत्यंत गहरे हैं। समाज और राष्ट्र की सारी समस्याओं का मूल व्यक्ति के भीतर छिपा है। इसीलिये देश के सभी वर्गों को एकसूत्र में जोड़ने के संकल्प के साथ संघ आगे बढ़ेगा क्योंकि जब तक व्यक्ति का चरित्र, दृष्टि और आचरण नहीं बदलते, तब तक कोई भी व्यवस्था स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं हो सकती। संघ व्यक्ति-निर्माण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को बदलने की दीर्घकालिक साधना कर रहा है। यही कारण है कि संघ के कार्य का परिणाम केवल शाखाओं या कार्यक्रमों में नहीं मापा जा सकता, बल्कि उस अदृश्य लेकिन ठोस नैतिक शक्ति एवं सशक्त राष्ट्रीय भावना में देखा जा सकता है, जो धीरे-धीरे समाज की दिशा बदल रही है।

भागवत ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने विविधता को भारत की विशेषता बताया और समाज में विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर चेताया। उन्होंने पंच परिवर्तन की संकल्पना भी प्रस्तुत की जिसमें आत्मजागरूकता, परिवारिक मूल्य, नागरिक अनुशासन और पर्यावरण के



प्रति संवेदनशीलता को जोड़ा गया है। इस संदेश के सकारात्मक पक्ष अनेक हैं। यदि इसे गंभीरता से अपनाया जाए तो यह देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को नई दिशा दे सकता है। स्थानीय उद्योगों, हस्तशिल्प और कृषि को बढ़ावा देने से रोजगार का सृजन होगा और आर्थिक आत्मसम्मान मजबूत होगा। स्वदेशी पर बल देने से विदेशी निर्भरता घटेगी और देश की सुरक्षा व नीति संबंधी स्वतंत्रता बढ़ेगी। यदि समाज के स्तर पर भी इस सोच को अपनाया जाए तो उपभोक्तावाद के स्थान पर संवेदनशीलता और सेवा भाव विकसित होगा। विविधता के सम्मान और सामाजिक सद्भाव के आग्रह से राष्ट्र अधिक एकजुट और शक्तिशाली बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस आत्मनिर्भर भारत का आह्वान कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। यह संदेश देश की घरेलू क्षमताओं को सशक्त बनाने, आयात पर निर्भरता घटाने और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ विकास की दिशा को व्यापक सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ता है, जिसमें महात्मा गांधी की 'स्वदेशी अपनाओ' और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 'अंत्योदय' की परिकल्पना स्पष्ट तौर पर समाहित है।

स्वदेशी और स्वावलंबन की राह पर चलकर ही नया भारत-सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकता है। इस बात को सरकार भी रेखांकित कर चुकी है और अब संघ प्रमुख ने भी दोहरा दिया। यह समय की मांग है कि स्वदेशी और स्वावलंबन पर तब तक बल दिया जाए, जब तक वांछित सफलता न मिल जाए। जहां सरकार को स्वदेशी की राह को आसान करना होगा, वहीं समाज को सहयोग देने के लिए तत्पर रहना होगा। इस उम्मीद में नहीं रहा जाना चाहिए कि अमेरिका के साथ शीघ्र ही आपसी व्यापार समझौता हो जाएगा। एक तो जब तक ऐसा हो न जाए तब तक चैन से नहीं बैठा जा सकता और दूसरे, यदि ऐसा हो जाए तो भी भारत को स्वदेशी और स्वावलंबन की राह पर चलना छोड़ना नहीं चाहिए। व्यापारिक साझेदारों पर निर्भरता लाचारी में नहीं बदलनी चाहिए। वास्तव में इस स्थिति से बचने का ही उपाय है स्वदेशी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। परंतु इस संदेश के साथ कई चुनौतियां और सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी आपस में गुंथी हुई है कि किसी भी देश का पूर्ण स्वावलंबन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अनेक तकनीकें और कच्चे माल अब भी हमें विदेशों से ही प्राप्त करने होते हैं। यदि स्वदेशी को बढ़ावा देने के नाम पर

विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध या अधिक शुल्क लगाए जाते हैं तो यह व्यापार युद्ध और आर्थिक तनाव को जन्म दे सकता है। इस संदेश की सफलता केवल भाषणों और भावनात्मक नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि ठोस नीतियों, बजट, शोध और योजनाओं के आधार पर इसे अमल में लाना होगा।

सामाजिक दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा केवल एक सांस्कृतिक या राजनीतिक रंग में न ढल जाए। यह तभी कारगर होगा जब इसे हर वर्ग, हर धर्म और हर क्षेत्र का साझा लक्ष्य बनाया जाएगा। नागरिकों की आदतों और व्यवहार में बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन यदि यह बदलाव शिक्षा, प्रोत्साहन और जनचेतना के माध्यम से लाया जाए तो यह नारा समाज में गहरी जड़ें जमा सकता है। संघ प्रमुख का यह संदेश नए भारत की दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें बताता है कि हमें अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति पर गर्व करना चाहिए, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से सशक्त होना चाहिए और विश्व के साथ संवाद स्थापित करते हुए भी अपनी स्वायत्तता को बनाए रखना चाहिए। किंतु इसके लिए आलोचनात्मक विवेक, व्यावहारिक सोच और निरंतर समीक्षा की आवश्यकता है। आज विभिन्न देशों की परस्पर मित्रता का आधार अपने-अपने आर्थिक-कूटनीतिक हित हैं। इन स्थितियों में सर्वोत्तम उपाय स्वदेशी को बल देते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाना है।

आज की वैश्विक परिस्थितियों पर दृष्टि डालें तो भागवत के विचार और भी प्रासंगिक हो उठते हैं। दुनिया हिंसा, आतंकवाद, युद्ध और उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ से त्रस्त है। पर्यावरण संकट दिन-प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। मानसिक तनाव और आत्मकेंद्रित जीवन-शैली ने मानव को भीतर से खोखला कर दिया है। इन परिस्थितियों में भारत ही वह देश है, जो एक वैकल्पिक जीवन-दर्शन दे सकता है। भारत के पास भौतिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक समृद्धि की धरोहर है। यही धरोहर भारत को विश्वगुरु बनने की पात्रता प्रदान करती है। संघ की शताब्दी वर्ष की सम्पूर्णता का उद्घोष केवल संघ के स्वयंसेवकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और विश्व के लिए एक संदेश है। यह संदेश है- स्वावलम्बी एवं स्वदेशी भावना को बदल देना, नए मनुष्य का निर्माण करना, गरीब को उठाना, धर्मों को जोड़ना, समाज में समरसता स्थापित करना और हिंदुत्व की व्यापक जीवन दृष्टि के आधार पर विश्व को दिशा देना। यह केवल भाषण नहीं, बल्कि एक संकल्प है। प

यह निजी विचार है।

वैश्विक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती दक्षिण एशियाई दरारें

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

दक्षिण एशिया आज जिस दौर से गुजर रहा है, वह केवल आंतरिक अस्थिरता की कथा नहीं है, बल्कि वैकि राजनीति की गहरी छायाओं से आच्छादित परिदृश्य भी है।

यह भू-भाग, जो कभी प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक बहुलता और समृद्ध परंपराओं का उद्गम स्थल रहा, आज अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के हितों की प्रयोगशाला और प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार तक, और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक, लगभग सभी देशों में उथल-पुथल, आंदोलनों और सत्ता संघर्ष का आलम है। इन घटनाओं ने क्षेत्र की स्थिरता को संकट में डाल दिया है। श्रीलंका इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 2022 में जब इस द्वीप राष्ट्र में आर्थिक संकट ने भयावह रूप लिया तब जनता ने राजपक्षे परिवार की सत्ता को उखाड़ फेंका। विदेशी कर्ज का बोझ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुप्रबंधन ने आम लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। यह आंदोलन सरकार-विरोधी आक्रोश भर नहीं था, बल्कि संकेत था कि जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा की जाएगी तो सत्ताधारी वर्ग के लिए कुसीं बचाना असंभव होगा। कुछ ही समय बाद बांग्लादेश में भी आक्रोश की लपटें उठीं। शेख हसीना की सरकार, जिसने विकास और आर्थिक प्रगति के नाम पर स्थायित्व कायम किया था, अचानक विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गई। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रश्न चिह्न ने आंदोलन को जन्म दिया। नेपाल की स्थिति और भी जटिल है। नेपाल का भूगोल, रणनीतिक स्थिति और भारत-चीन के बीच उसकी अहमियत ने इसे बाहरी हस्तक्षेप का सहज शिकार बना दिया है। वहां की राजनीति में लगातार बदलते गठबंधन, नेतृत्व की अस्थिरता और जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा ने असंतोष को हवा दी है।

राजतंत्र समर्थक और कट्टरपंथी ताकतें असंतोष को भुनाने में जुटी हैं, जिससे नेपाल की सामाजिक संरचना में नई दरारें पड़ रही हैं। इसी तरह म्यांमार, जहां सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, वर्षों से गृह युद्ध और विद्रोह की चपेट में है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। यहां विदेशी शक्तियों की भूमिका और भी स्पष्ट दिखती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव, चीन की गहरी आर्थिक पैठ और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन की लड़ाई ने म्यांमार को अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। पाकिस्तान की स्थिति भी किसी से

छिपी नहीं है। यहां एक ओर सेना और न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर होता जा रहा है। विदेशी कर्ज पर निर्भरता, मुद्रास्फ़ीति और बढ़ते आतंकी हमलों ने जनजीवन को असुरक्षित बना दिया है।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया दो महाशक्तियों-अमेरिका और चीन-की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। एक ओर चीन 'बेल्ट एंड रोड' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से पूरे क्षेत्र को अपनी आर्थिक-रणनीतिक पकड़ में लेना चाहता है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ 'क्वाड' जैसी साझेदारियों के जरिए इस प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा यह है कि दक्षिण एशियाई देशों की अंतराजिह्म की अंतर्गत प्रतिस्पर्धा में उनकी अपनी नहीं रह गई है। हर आंदोलन, हर सत्ता परिवर्तन और हर अस्थिरता के पीछे विदेशी छायाएं मंडराती दिखती हैं। यह क्षेत्र केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिन्द महासागर, मलक्का जलडमरूमध्य और हिमालयी गलियारों पर पकड़ बनाने की जद्दोजहेद ने बाहरी शक्तियों को यहां सक्रिय कर दिया है।

भारत, जो स्वयं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उपरती शक्ति है, के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती लेकर आती है। एक ओर उसे अपने पड़ोस की अस्थिरता का सामना करना है, तो दूसरी ओर बाहरी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करना है। दक्षिण एशियाई देशों की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण यह है कि शासक वर्ग ने जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं दी। लोकतंत्र चुनावों तक सीमित रह गया, जबकि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन का अभाव रहा। आर्थिक विकास का लाभ कुछ वगरे तक सीमित रहा, जिससे सामाजिक विषमता बढ़ी। यह असंतोष जब फूटता है, तो आंदोलन का रूप ले लेता है और जब यह आंदोलन विदेशी हितों से टकराता है, तो बाहरी शक्तियां अपने-अपने हित साधने के लिए उसे हवा देने से नहीं çekती हैं।

दक्षिण एशियाई दरारें केवल क्षेत्रीय संकट नहीं हैं, बल्कि वैकि व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती हैं। यदि यह क्षेत्र अस्थिर रहता है, तो न केवल एशिया, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और विकास प्रभावित होंगे। इसलिए आवश्यक है कि विदेशी शक्तियां यहां अपने-अपने हित साधने की बजाय क्षेत्रीय स्थिरता और जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। (लेख में विचार निजी हैं)

भारत ने आईएसएसए विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच के दौरान सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और श्रम गतिशीलता पर वैश्विक साझेदारी को मजबूत किया

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सामाजिक सुरक्षा सहयोग पर युगांडा, मलेशिया और पीईआरकेईएसओ के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं

भारत ने सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर प्रकाश डाला जो वर्ष 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 64 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, जिससे 940 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे

पीआईबी

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज मलेशिया के कुआलालंपुर में विश्व सामाजिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसएसएफ) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) के अध्यक्ष और मलेशिया तथा युगांडा के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और कौशल की पारस्परिक मान्यता, सुरक्षित श्रम गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। डॉ. मांडविया भारत सरकार की ओर से 'सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि' के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 प्राप्त करने के लिए मलेशिया दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के अध्यक्ष और पीईआरकेईएसओ के मुख्यकार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक

डॉ. मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा



संघ के अध्यक्ष और मलेशिया के सामाजिक सुरक्षा संगठन के पीईआरकेईएसओ के मुख्यकार्यकारी अधिकारी प्रो. दातो श्री डॉ. मोहम्मद अजमान के साथ बातचीत की। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा विस्तार में भारत की उपलब्धियों को आईएसएसओ द्वारा मान्यता दिए जाने पर आभार व्यक्त किया और आईएसएसओ में भारत के बड़े हुए प्रतिनिधित्व और मताधिकार का स्वागत किया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई-श्रम और राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए भारत के डिजिटल-फ़स्ट दृष्टिकोण पर भी जोर दिया।

आईएसएसए के अध्यक्ष ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के लिए बधाई दी तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कम समय में ही सामाजिक सुरक्षा कवरेज में हुए उल्लेखनीय विस्तार की सराहना की।

युगांडा के साथ बैठक

केंद्रीय मंत्री ने युगांडा की जेंडर, लेबर और सोशल डेवलपमेंट मंत्री, बेट्टी अमोंगी ओंगोम से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया और इस वर्ष के आरंभ में नई दिल्ली में 23 वर्षों के बाद आयोजित भारत-युगांडा संयुक्त व्यापार

सहयोग सत्र के पुनः आरंभ होने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने लोक निर्माण, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और टेली-मेडिसिन में साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की, जिससे आर्थिक जुड़ाव मजबूत होगा और कुशल पेशेवरों का आदान-प्रदान बढ़ेगा।

डॉ. मनसुख मांडविया ने वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने में भारत की उपलब्धियों को साझा किया और भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभाओं को अवसरों से प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने में युगांडा का समर्थन करने की इच्छा भी

व्यक्त की।

युगांडा ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से ई-श्रम और राष््रीय करियर सेवा को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई।

मलेशिया के साथ बैठक

डॉ. मनसुख मांडविया ने मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री स्टीवन सिम ची कियोंग के साथ चर्चा की और आईएसएसए मंच की सफल मेजबानी के लिए मलेशिया को बधाई दी। यह मंच वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की मलेशिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉ. मनसुख मांडविया ने देश के पेशेवर और कुशल कार्यबल के माध्यम से मलेशिया के श्रम बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तत्परता दोहराई।

मंत्रियों ने आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत-मलेशिया की रणनीतिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया।

भारत ने कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम (ईएसआईसी) और पीईआरकेईएसओ के बीच प्रस्तावित सहयोग ज्ञापन पर आगे बढ़ने की अपनी तत्परता की पुष्टि की, जिसकी पहल विदेश मंत्रालय के साथ पहले ही की जा चुकी है।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) को वैश्विक समुदाय के गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

मलेशिया ने डॉ. मांडविया को वर्ष 2026 में प्लेटफार्म श्रमिकों पर आयोजित शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है।

ट्राई ने निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने पर अनुशंसाएं जारी कीं

पीआईबी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज चार 'ए+' श्रेणी के शहरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और नौ 'ए' श्रेणी के शहरों अर्थात हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और नागपुर में डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवा शुरू करने के लिए नियम और शर्तों तथा आरक्षित मूल्य के साथ +निजी रेडियो प्रसारकों के लिए एक डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने+ पर अपनी अनुशंसाएं जारी की हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 23 अप्रैल 2024 के अपने संदर्भ के माध्यम से निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण

टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जो ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके बाद, 8 जनवरी 2025 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई। प्राप्त सभी टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों पर विचार करने और मुद्दों के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: नए प्रसारकों द्वारा डिजिटल रेडियो सेवाएं सिमुलकास्ट मोड में शुरू की जानी चाहिए। विद्यमान एनालॉग एफएम रेडियो प्रसारकों को भी स्वेच्छिक आधार पर सिमुलकास्ट मोड में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रस्तावित सिमुलकास्ट मोड उन्हें निर्धारित स्पॉट फ्रीक्वेंसी पर एक एनालॉग, तीन डिजिटल और एक डेटा चैनल प्रसारित

करने में सक्षम बनाएगा।

भारत में वीएचएफ बैंड II में डिजिटल रेडियो प्रसारण आरंभ करने के लिए एकल डिजिटल रेडियो प्रौद्योगिकी मानक अपनाया जाना चाहिए।

सरकार को देश में तैनाती के लिए उपयुक्त डिजिटल रेडियो प्रौद्योगिकी का चयन या तो मुख्य हितधारकों अर्थात रेडियो प्रसारकों और रेडियो रिसीवर निर्माताओं के साथ परामर्श करके करना चाहिए या स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के चयन को शामिल करके या सरकार द्वारा उपयुक्त समझौते जाने वाली किसी अन्य विधि का उपयोग करना चाहिए।

सरकार को श्रेणी 'ए+' के चार शहरों और श्रेणी 'ए' के 7?नौ शहरों में से प्रत्येक के लिए एकल प्रौद्योगिकी परिदृश्य में

फ्रीक्वेंसी योजना तैयार करनी चाहिए और उसे सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में रखना चाहिए।

नए चैनलों के लिए फ्रीक्वेंसी दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 4(4) के अनुसार नीलामी के माध्यम से आवंटित की जानी चाहिए।

डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए नीलामी के माध्यम से फ्रीक्वेंसी के सफल आवंटन के तुरंत बाद, विद्यमान एफएम रेडियो प्रसारकों को स्वेच्छिक आधार पर सिमुलकास्ट मोड में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए।

नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि से 6 महीने की समय-सीमा विद्यमान प्रसारकों को सिमुलकास्ट मोड में स्थानांतरित करने का विकल्प चुनने के लिए दी जानी चाहिए।

मनसुख मांडविया ने मलेशिया में भारतीय समुदाय से बातचीत की



पीआईबी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज मलेशिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत की विकास यात्रा को सुदृढ़ बनाने और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। मलेशिया में 29 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। डॉ. मांडविया ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित रखने और भारत-मलेशिया संबंधों को मजबूत बनाने

तथा मलेशिया की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय समुदाय की सराहना की। डॉ. मनसुख मांडविया ने दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 150 से अधिक भारतीय कंपनियां मलेशिया में काम कर रही हैं, जबकि मलेशिया की लगभग 70 कंपनियां भारत में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार, तेल और गैस, बिजली और पर्यटन आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं। डॉ. मांडविया ने विदेशों में भारतीय कामगारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित हुए डॉ. लूनेश कुमार वर्मा



लोकशक्ति संवाददाता

वक्ता मंच (छत्तीसगढ़ प्रदेश की सामाजिक - साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था) एवं दैनिक दबंग स्वर के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. लूनेश कुमार वर्मा को हिंदी सेवा सम्मान - 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हिंदी भाषा के प्रति उनकी सृजनात्मक साधना, प्रेरणादायी कृतियों और समाज में हिंदी सेवा के उल्लेखनीय

योगदान के लिए प्रदान किया गया। कार्यक्रम में डॉ लूनेश कुमार वर्मा की हिंदी हाइकु संग्रह 'नई उड़ान' का विमोचन किया गया। विमोचन अवसर पर डॉ. लूनेश कुमार वर्मा ने हाइकु की विशेषताओं को विस्तार से बताया। उन्होंने 'नशा नाश की जड़ है' पर आधारित हाइकु जोश व? होश- किशोर मदहोश, पल खामोश, पढ़ा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पं. पी. के. त्रिवेदी (प्रधान

संपादक, दबंग स्वर), राजेश पराते(अध्यक्ष, वक्ता मंच), शुभम साहू, एकता वर्मा, नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा सहित विभिन्न विधा के साहित्यकारों, कवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सभी साहित्यकारों सहित संस्कृत भाषा के प्रचारक पं. चन्द्रभूषण शुक्ला ने डॉ. लूनेश कुमार वर्मा के हिंदी लेखन की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दीं।



रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति

रायपुर, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान किए जाने पर आभार व्यक्त कर कहा है कि देश के अन्नदाताओं को लगातार समृद्ध और सशक्त बनाने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में मातृ-शक्ति के साथ ही गरीब और किसानों के आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण के लिए क्रांतिकारी कदम सतत उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। निःसंदेह यह सरकार छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी।

यूपीएससी 2022 परिणाम के भ्रामक विज्ञापनों के लिए दृष्टि आईएस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

एजेंसी

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने यूपीएससी 2022 परिणाम के भ्रामक विज्ञापनों के लिए दृष्टि आईएस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2022 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए दृष्टि आईएस (वीडीके एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दृष्टि आईएस ने अपने विज्ञापन में सफल उम्मीदवारों के नाम और चित्रों के साथ +यूपीएससी सीएसई 2022 में 216 से अधिक उत्तीर्ण होने का प्रमुखता से दावा किया था।

यद्विप, जांच के बाद सीसीपीए ने पाया कि दावा भ्रामक था और इसमें इन अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों के प्रकार और अवधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई थी।

जांच से पता चला कि दृष्टि आईएस द्वारा दावा किए गए 216 उम्मीदवारों में से, 162

(75 प्रतिशत) ने ही यूपीएससी सीएसई के प्रारंभिक और मुख्य चरणों में स्वतंत्र रूप से उत्तीर्ण होने के बाद, संस्थान के निःशुल्क साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम (आईजीपी) में भाग लिया था। केवल 54 छात्रों ने आईजीपी+ अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था।

इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाने से अभ्यर्थियों और अभिभावकों को यह विश्वास हो गया कि यूपीएससी परीक्षा के सभी चरणों में उनकी सफलता के लिए दृष्टि आईएस उत्तरदायी है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के तहत एक भ्रामक विज्ञापन है।

दृष्टि आईएस द्वारा बार-बार उल्लंघन: सीसीपीए ने यह भी नोट किया कि इसी तरह के आचरण के लिए दृष्टि आईएस पर लगाया गया यह दूसरा जुर्माना है। इससे पहले, प्राधिकरण ने +यूपीएससी सीएसई 2021 में 150+ चयन+ के भ्रामक दावे के लिए दृष्टि आईएस के विरुद्ध सितंबर 2024 में अंतिम आदेश पारित किया था। संस्थान ने यूपीएससी सीएसई 2021 में 150+

चयन के अपने दावे के मुकाबले 161 उम्मीदवारों का विवरण प्रस्तुत किया। उस मामले में भी, यह पाया गया कि इन 161 उम्मीदवारों में से 148 ही आईजीपी में नामांकित थे, 7 मेन्स मेंटरशिप प्रोग्राम में नामांकित थे, 4 जीएस फंडेशन प्रोग्राम में नामांकित थे, 1 वैकल्पिक पाठ्यक्रम में और शेष 1 उम्मीदवार का विवरण नहीं दिया गया था। सीसीपीए ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और भ्रामक विज्ञापन को बंद करने का निर्देश दिया था।

पहले दंडित किए जाने और चेतावनी के बावजूद, दृष्टि आईएस ने एक बार फिर 2022 के परीक्षा परिणामों के लिए अपने दावे को बढ़ाकर +216+ चयन+ करके उसी तरह कार्य किया, जिससे उपभोक्ता संरक्षण मानदंडों का बार-बार गैर-अनुपालन और अवहेलना प्रदर्शित हुई।

ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने से भावी छात्रों और अभिभावकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(9) के तहत सूचित विकल्प बनाने के उनके अधिकार से

वंचित होना पड़ता है। ऐसे विज्ञापन झूठी उम्मीदें पैदा करते हैं और उपभोक्ता के निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं, खासकर जब तथ्यों के पारदर्शी प्रकटीकरण के बिना बड़े दावे किए जाते हैं।

अब तक, सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 54 नोटिस जारी किए हैं। 26 कोचिंग संस्थानों पर 90.6 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही ऐसे भ्रामक दावे बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीसीपीए ने पाया कि ऐसे सभी संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में सफल अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन के समान है। प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि सभी कोचिंग संस्थानों को अपने विज्ञापनों में सूचना का सत्य प्रकटीकरण सख्ती से सुनिश्चित करना चाहिए ताकि छात्र अपने शैक्षणिक विकल्पों के संबंध में निष्पक्ष और सूचित निर्णय ले सकें।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को लगातार दूसरे वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम) तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को तृतीय पुरस्कार मिलने पर दी शुभकामनाएं



पीआईबी। डॉ जितेंद्र सिंह, माननीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री महोदय ने, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को, राजभाषा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा, वर्ष 2024-25 के संबंध में, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार(प्रथम) तथा पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग को, तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाने के अवसर पर, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं दीं।

विधायक राघवेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बिजली कार्यालय का घेराव

भाजपा सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेसजन

संवाददाता । अकलतरा /

जिला कांग्रेस कमटी अध्यक्ष विधायक राघवेन्द्र कुमार सिंह ने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर के बिजली कार्यालय का घेराव कर भाजपा सरकार के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन किया। यह आंदोलन बिजली बिल हॉफयोजना को बंद करने तथा बिजली दरों में हुई भारी बढ़ोतरी के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि अविलम्ब निर्णय वापस नहीं लिया गया तो जनआंदोलन और तेज किया जाएगा।

विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता पर असहनीय आर्थिक बोझ बढ़ गया है। आम उपभोक्ता महंगे बिजली बिलों से त्रस्त हैं और जगह-जगह अघोषित बिजली कटौती से आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कहा कि भाजपा जनहित की योजनाओं को समाप्त कर रही है और जनता को अंधेरे में धकेल रही है। विधायक ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस सदैव जनता के हक़ की लड़ाई लड़ेगी और किसी भी



कीमत पर उपभोक्ताओं के साथ अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। इस घेराव प्रदर्शन कार्यक्रम में मंजू सिंह, इमरान खान, दिवाकर राणा, खुलन

सोनवानी, महेश्वर टंडन ,राज सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

गेमन पुल, भुंडी पुल व जांजगीर-पिथमपुर मार्ग निर्माण की मिलेगी शीघ्र स्वीकृति

जांजगीर चांपा / विधायक ब्यास

कश्यप ने हसदेव नदी पर निर्मित गेमन पुल के स्थान पर नवीन पुल निर्माण, लछनपुर के पास भुंडी नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण तथा जांजगीर-पिथमपुर मार्ग के शीघ्र निर्माण के लिए लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव को पत्र प्रेषित किया था। विधायक जी द्वारा प्रेषित पत्र को आवश्यक कार्यवाही के लिए लोक निर्माण विभाग के सचिव को अग्रेषित किया गया है। ज्ञात हो कि उक्त कार्यों की स्वीकृति के लिए विधानसभा के बजट सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में जांजगीर-चांपा विधायक ब्यास कश्यप के द्वारा प्रमुखता से मांग की गई थी। विधायक की मांग पर इन कार्यों को बजट में शामिल किया गया था। कार्यों में तीव्रता लाने के लिए रायपुर प्रवास के दौरान ब्यास कश्यप अनेकों बार विभागीय मंत्री से मिले तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में 28 अगस्त को रायपुर प्रवास के दौरान ब्यास कश्यप ने उक्त कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए पत्र लोक निर्माण मंत्री को सौंपते हुए निवेदन किया कि ये सभी कार्य जहजित में अत्यावश्यक हैं तथा ये वर्षों पुरानी मांगें हैं। हसदेव नदी पर निर्मित गेमन पुल अत्यंत जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। इसको जैसे-तैसे मरम्मत कराकर कार्य लिया जा रहा है। शीघ्र ही नये पुल का निर्माण नही किया जाता है तो कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। इसी



प्रकार ग्राम लछनपुर के पास भुंडी नाला में निर्मित पुल वर्षों पुराना है तथा रोड लेवल से काफी नीचे बना है जिससे बरसात के दिनों में इस पुल के ऊपर से पानी बहता है। इस पुल पर कई गंभीर घटनाएं भी घटित हो चुकी है। जांजगीर-पिथमपुर मार्ग की बात करें तो यह मार्ग अत्यंत ही खराब हो चुका है। मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हैं। इस मार्ग से आवागमन अत्यंत दुष्कर है। इस मार्ग में नवीन

सड़क निर्माण के लिए ग्रामवासी चक्काजाम भी कर चुके हैं। विधायक ब्यास कश्यप की बातों को लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव ने बड़ी गंभीरता से सुना तथा उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए पत्र सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया है। उम्मीद है कि उपरोक्त सभी कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होंगे तथा लोगों की समस्याओं का निदान हो सकेगा।

बुराई या अधर्म चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो अंत में उसका विनाश निश्चित है : मेघराज चंद्राकर

भरेंगांव में रामलीला का मंचन कर किया रावण दहन

राजनांदगांव। ग्राम भरेंगांव में नवरात्रि पर्व विजयादशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्रीय जनपद पंचायत सदस्य मेघराज (मेघा) चंद्राकर ने बताया कि दशहरा आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया जिसमें गांव के ही कलाकार द्वारा भव्य रामलीला स्व.जवाहरलाल चंद्राकर समिति एवं ग्राम वासियों के सहयोग से रामलीला का मंचन प्रतिदिन किया गया और रावण की भव्य पुतला गोलू पटेल के द्वारा बनाया गया था। जनपद सदस्य मेघा चंद्राकर ने आगे बताया कि गांव के शीतला मंदिर में नवरात्रि के दौरान प्रसादी वितरण,रावण दहन, रामलीला एवं मूर्ति विसर्जन माता के जस गीतों भजनों के साथ किया गया। रावण दहन के दौरान जनपद सदस्य मेघराज चंद्राकर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत, सामाजिक कुरीतियों के अंत और सकारात्मकता के संदेशों का उद्बोधन देते हुए कहा कि लोगों को लोभ, अहंकार और अन्याय पर सच्चाई की विजय का संदेश देते हुए, स्वयं को बुराई से दूर रखने और समाज में अच्छाई का प्रसार करने के लिए प्रेरित



किया. उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत रावण दहन के

माध्यम से संदेश हैं कि बुराई या अधर्म चाहे कितना भी विशाल क्यों

न हो, अंत में उसका विनाश निश्चित है और सच्चाई की जीत ही होती है।

बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूँजी- कलेक्टर

कलेक्टर ने कहा- देखभाल, सम्मान और आत्मीयता ही बुजुर्गों की असली दवा

कोरिया, । अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने जिले के सभी बुजुर्गों को स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि बुजुर्गों का सम्मान, देख और आत्मीयता ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि चाहे पाश्चात्य संस्कृति कितनी भी आगे जाए, भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों के प्रति आदर और सेवा की परंपरा का कोई विकल्प नहीं है।

बुजुर्गों की कहानियां अलग-अलग, दर्द लगभग एक जैसा

कलेक्टर ने बताया कि वे समय-समय पर वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों से मुलाकात करती हैं और उनकी सेहत व समस्याओं की जानकारी लेती हैं। उन्होंने कहा, हर बुजुर्ग की अपनी कहानी है, लेकिन उनका दर्द लगभग

एक जैसा है। इसीलिए हमें हर समय उनका सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। यही मानवीय संवेदना का सबसे बड़ा उदाहरण है।

नई पीढ़ी से की अपील

कलेक्टर ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने घर और समाज के बुजुर्गों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराएँ, आवश्यक उपचार उपलब्ध कराएँ और आत्मीयता से उनके साथ समय बिताएँ। उन्होंने कहा, बुजुर्गों के साथ बैठना, उनसे बातें करना और उनकी समस्याएँ सुनना ही उनके लिए सबसे बड़ी दवा है।

कर्मचारियों को दिए निर्देश

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी कहा कि जब भी कोई बुजुर्ग कार्यालय में आए तो उन्हें बैठने के लिए अवश्य कहें, पानी पिलाएँ और उनकी समस्या का यथासंभव समाधान करें। उन्होंने कहा, सरकारी सेवाओं का असली मूल्य तभी है जब समाज का सबसे कमजोर और सबसे वृद्धजन सहजता से लाभ उठा सके।

सुंदरा में 51 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य जगराता, समिति ने कलाकार को किया सम्मानित

राजनांदगांव।

शहर से लगे ग्राम सुंदरा में 51 वर्ष पूर्ण होने के शुभावसर पर हुआ भव्य जगराता कार्यक्रम कुंदरू पारा बालोद के आराधना बालिका जस परिवार के द्वारा ग्राम सुंदरा में दुर्गा अष्टमी के शुभ अवसर पर जगराता भजन कीर्तन का आयोजन सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के तत्वावधान मे किया गया

इस बीच मातारानी के जसगीतों का समा बांधा सभी भक्तो ने जगराता कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया और इस दुर्गा अष्टमी को यादगार ऐतिहासिक बनाया आयोजक सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति अटल चौक सुंदरा ने शानदार पस्तुती के लिए कलाकारों को किया सम्मानित।



राजनांदगांव व डोंगरगढ़ में पर्यटक सूचना केंद्रों का हुआ संयुक्त लोकार्पण

राजनांदगांव

माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी और माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री नीलू शर्मा जी रहे उपस्थित।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ओर से राजनांदगांव और डोंगरगढ़ को पर्यटन विकास की नई सौगात के तहत पर्यटन सूचना केंद्र मिला। आज 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को संध्या 6.30 बजे गौरव पथ स्थित चौपाटी, विश्राम गृह के सामने आयोजित समारोह में राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ में नवनिर्मित सूचना केंद्रों का संयुक्त शुभारंभ और लोकार्पण माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया ।

डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने संबोधन में कहा कि टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने अध्यक्ष बनते ही अपने संक्षिप्त कार्यकाल में उल्लेखनीय कार्य किया है,राज्य के पर्यटन विकास के लिए ये शुभ संकेत है।

इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय सांसद राजनांदगांव श्री संतोष पांडे जी ने कहा कि राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में पर्यटन सूचना केंद्र की स्थापना से जिले सहित देशी विदेशी पर्यटक छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की जानकारी के साथ ही जिले की पर्यटन विशेषताओं से भी परिचित होंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में



अध्यक्ष नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ श्री रमन डोंगरे,पूर्व विधायक श्री रामजी भारती व श्री विनोद खांडेकर,माननीय महापौर राजनांदगांव श्री मधुसूदन यादव, माननीय अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक श्री सचिन बघेल तथा अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव की गरिमामयी उपस्थिति रही। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने अपने स्वागत भाषण और

प्रतिवेदन में कहा कि इन सूचना केंद्रों की स्थापना से पर्यटकों को यात्रा मार्ग, ठहरने की सुविधा, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों तथा स्थानीय कला-संस्कृति की जानकारी सहज रूप से मिल सकेगी। यह पहल जिले में पर्यटन गतिविधियों को पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव की को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। आयोजन में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की उपमहाप्रबंधक श्रीमती पूनम

शर्मा,वरिष्ठ अधिकारीगण,जिले के जनप्रतिनिधियों सचिन गोलछा जी, खूब चंद पारख जी, कोमल सिंह राजपूत जी, पार्षद खेमिन यादव जी, मोना गोसाईं जी, मणि भास्कर जी जी,रेणु मैश्राम जी, लता मोहोबिया जी, माधुरी जैन जी,मंजू साहू जी, संगीता शुक्ला,सुधा पवार, अनिता प्रंसिस, और सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी भी रही।

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

भानुप्रतापपुर काष्ठागार (पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल) के ई-नीलाम का संक्षिप्त विवरण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत काष्ठागार भानुप्रतापपुर एवं बांसागार कराटी संग्रहित ईमारती काष्ठ ६ बल्ली ६ व्यापारिक बांस का निम्न दर्शाये गये स्थल में भण्डारित है। जिसका निर्वहन ई-नीलाम तिथि 0७.१०.२०२५ को किया जावेगा तदनुसार इच्छुक बोलीदारों से अनुरोध है कि घोष विक्रय में भाग लेंगे । नीलाम में प्रस्तावित मात्र कम या अधिक हो सकती है। बोली लगाने से पूर्व कृपया वनोपज का निरीक्षण कर लेंगे। घोष विक्रय की शर्तों एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में संबंधित वनमंडल से प्राप्त की जा सकती है।

वनमंडल का नाम	काष्ठागार का नाम	स्थान/नीलाम दिनांक व समय
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल	काष्ठागार भानुप्रतापपुर	काष्ठागार भानुप्रतापपुर नीलाम दिनांक 07.10.2025 प्रातः 09:00 बजे से

:- अनुमानित मात्रा काष्ठ एवं बल्लियाँ :-

अ. क्र.	प्रजाति	नया वनोपज		अविक्रित वनोपज		योग	
		काष्ठ घ.मी	बल्ली	काष्ठ घ.मी	बल्ली	काष्ठ घ.मी	बल्ली
1	सागीन	70	0	148	439	218	439
2	साल	8	0	33	0	41	0
3	बीजा	0	0	59	64	59	64
4	साजा	39	0	153	193	192	193
5	हल्दू/मुण्डी	0	0	63	0	63	0
6	सलिस/ मोदे	4	0	11	0	15	0
7	तिन्सा	0	0	8	0	8	0
8	घायड़ा	0	0	68	0	68	0
10	तेन्दू	0	0	72	0	72	0
11	अन्य	26	0	97	0	123	0
योग :-		147	0	712	696	859	696

नीलाम हेतु प्रस्तावित व्यापारिक बांस :-

क्र	वनमण्डल	बांसागार भानुप्रतापपुर	नग	नोटन
1	पूर्व वनमंडल भानुप्रतापपुर	व्यापारिक बांसागार भानुप्रतापपुर (पुराना लॉट)	8470	25.608

दूरभाष क्रमांक – पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल (07850-252223)

- कृताओं को ई-नीलाम के पूर्व एम.एस.टी.सी. ई-कामर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
- कृताओं को ई-नीलाम के पूर्व कय लॉटों के अपस्टेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई.एम.डी.की राशि जमा करना अनिवार्य है।
- लॉट की थप्पी चुकी एवं फोटो एम.एस.टी.सी.ई-कामर्स पोर्टल में अपने आईडी से लॉगइन करके देख सकते हैं।
- ई-ऑक्शन में लॉट कय के पश्चात् प्रथम कृता को 40 सेकंड का समय प्राप्त होगा उसी लॉट में अन्य कृताओं द्वारा 40 सेकंड के पूर्व कय करने पर 30 सेकंड का समय प्राप्त होगा।

वनमंडलधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल
भानुप्रतापपुर

G-252603919/3

खास खबर

20 अक्टूबर तक प्रमाण पत्र जमा कराएं निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी

कोरबा, नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों, पेंशनरों से कहा गया है कि वे जीवित प्रमाण पत्र तीन-तीन प्रतियों में 20 अक्टूबर 2025 तक नगर निगम कार्यालय कोरबा के साकेत भवन स्थित स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से जमा कराएं ताकि उनके मासिक पेंशन भुगतान में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित न हो।

निगम के उपायुक्त व स्थापना प्रभारी पवन वर्मा ने उक्ताशय की सूचना जारी कर आगे कहा है कि निर्धारित तिथि तक जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर मासिक पेंशन भुगतान अवरूद्ध होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों, पेंशनरों की स्वयं की होगी, अतः उक्त अवधि तक प्रमाण पत्र अवश्य जमा करा देंवें।

बिजली बिल में वृद्धि का युवा कांग्रेस ने किया विरोध

कोरबा, । जिले सहित राज्य में बिजली बिलों में हुई अचानक बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं के माथे पर चिंता की नई लकीरें खींच दी हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और बिजली कार्यालय के बाहर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बिजली बिलों की प्रतियां जलाकर सरकार पर «जनविरोधी नीतियां» अपनाने का आरोप लगाया।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। «बिजली चोर गद्दी छोड़», «जनविरोधी सरकार मुर्दाबाद» जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पार्टी नेताओं ने कहा कि पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, ऐसे में बिजली बिलों की बढ़ोतरी ने जनता की कमर तोड़ दी है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। उनका कहना था कि गरीब और मध्यम वर्ग का बजट पहले ही चरमराया हुआ है, अब बिजली बिलों की मार ने घरों की रसोई तक प्रभावित कर दी है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने जनता से अपील की कि वे इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सड़क से विधानसभा तक उग्र आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ने पर इसे पूरे प्रदेश में जनांदोलन का रूप दिया जाएगा।

प्रदर्शन स्थल पर माहौल बेहद आक्रोशपूर्ण रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर बिजली बिल बढ़ोतरी का विरोध दर्ज था। पुलिस बल भी एहतियातन मौके पर मौजूद रहा और सुरक्षा व्यवस्था सभाले रहा। कांग्रेस नेताओं ने दोहराया कि उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर सरकार ने आम जनता की आवाज को अनसुना किया तो इसे बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा।

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत स्वस्थ माँ दिवस पर आयोजित शिविरों में 9047 हितग्राहियों की स्क्रीनिंग

कोरबा, संवाददाता। जिले में 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में में शिविर लगाकर हितग्राहियों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, पोषण आहार तथा स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विकासखण्डों में सोमवार 29 सितंबर को स्वस्थ माँ दिवस थीम पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया साथ ही साथ ही घंटाघर में आयोजित रामलीला, गरबा मैदान स्वास्थ्य विभाग की कॉलोनी, दशहरा मैदान, एनटीपीसी, लाल मैदान सीएफईबी में उपस्थित महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया गया जिसमें नौ हजार 47 लोगों की विभिन्न बिमारियों की स्क्रीनिंग किया गया। एनसीडी से संबंधित हावपरटेशन के पांच हजार 20,

रिक्त निजी भूखण्डों की गंदगी, शहर की स्वच्छता को कर रही प्रभावित, आयुक्त ने भूखण्ड मालिकों को नोटिस देने दिए निर्देश, साथ ही समझाईश भी दी

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने रविशंकर नगर जोनांतर्गत विभिन्न आवासीय क्षेत्रों, कालोनियों, मुख्य मार्गों, संपर्क सड़कों की साफ-सफ़ाई का लिया जायजा

कोरबा, आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने शहर में रिक्त निजी भूखण्डों में पसरी गंदगी पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित भूखण्ड मालिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आयुक्त पाण्डेय ने इन भूखण्डों के मालिकों से समक्ष में चर्चा भी की तथा कहा कि रिक्त भूखण्डों की गंदगी शहर की स्वच्छता को प्रभावित कर रही है एवं शहर को साफ-सुथरा रखने की दिशा में निगम द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों को भी झटका लग रहा है, अतः वे इन भूखण्डों की सफाई कराएं, भूखण्डों को सुरक्षित स्वरूप देते हुए यह देखें कि वहाँ पर पुनः गंदगी न फेंकी जाए।

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने अपने प्रातः भ्रमण के दौरान रविशंकर नगर जोनांतर्गत विभिन्न आवासीय क्षेत्रों, कालोनियों, मुख्य व संपर्क सड़कों का भ्रमण कर साफ-सफ़ाई कार्यों का जायजा लिया। यहाँ उल्लेखनीय है



कि आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के द्वारा नियमित रूप से अधिकारियों की टीम के साथ निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों, वार्ड व बस्तियों का भ्रमण कर वहाँ की साफ-सफ़ाई व नागरिक सेवाओं व सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आयुक्त पाण्डेय रविशंकर नगर के वार्ड क्र. 26 की विभिन्न कालोनियों, आवासीय क्षेत्रों, मुख्य मार्गों व संपर्क सड़कों आदि में

पैदल भ्रमण करते हुए वहाँ की साफ-सफ़ाई व्यवस्था के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान आवासीय क्षेत्रों में रिक्त निजी भूखण्डों में पसरी गंदगी पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की तथा संबंधित भूखण्ड स्वामियों को नोटिस जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर आयुक्त पाण्डेय ने कुछ भूखण्ड स्वामियों से समक्ष में चर्चा भी की तथा उन्हें समझाईश देते

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक हुई आयोजित

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक हुई आयोजित

0-निगमायुक्त आशुतोष पांडेय ने विभागावार कार्यों की समीक्षा कर निराकरण हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कोरबा, संवाददाता। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन में निगम आयुक्त कोरबा आशुतोष पांडेय ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करने एवं आमजनों को प्राथमिकता से लाभावित करने के निर्देश दिए। बैठक में निगमायुक्त पाण्डेय ने जिले में संचालित शासकीय कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी लेते हुए योजनाओं का आमजनों को प्राथमिकता से लाभ पहुँचाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने आमजनों को राहत पहुँचाने हेतु जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन पर



गम्भीरता से ध्यान देने की बात कही।

उन्होंने जिले में आयुष्मान कार्ड, व्यवन्दन कार्ड निर्माण कार्य मे प्रगति लाने एवं शीघ्रता से वंचित लोगों को लाभोहित करने के निर्देश दिए। साथ ही वंचितों के आधार अपडेशन कार्य को भी जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने हाथी प्रभावित क्षेत्रों एवं लो वोल्टेज की समस्या वाले इलाकों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की समस्या न हो। युक्तियुक्त करण के पश्चात जाँइन नही

करने वाले शिक्षकों पर भी गम्भीरता से कार्यवाही करने की बात कही।

निगमायुक्त ने सभी विभागों को ई ऑफिस के माध्यम से ही सभी फ़इलें आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। वनाधिकार पट्टा के लम्बित प्रकरणों को भी शीघ्रता से जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित कराकर पत्र हितग्राहियों को वितरित कराने की बात कही।उन्होंने आरबीसी 6-4 व सड़क दुर्घटना में होने वाले मृत्यु के प्रकरणों को समीक्षा करते हुए यथाशीघ्र लंबित आवेदनों की जांच करने दस्तावेजों की पूर्ति कर पीड़ित परिजनों को राहत दिलाने के

निर्देश दिए। पाण्डेय ने विभिन्न विभागों में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित सभी आवेदनों को जल्द से जल्द जांच कर निराकृत करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पंचायत विभाग एवं नगरीय निकाय जैसे विभागों से सम्बंधित टीएल के प्रकरण आमजनों के हितों से जुड़े होते हैं, इस हेतु इनका निराकरण यथाशीघ्र होनी चाहिए , जिससे लोगों को फ़यदा मिले एवं उनका शासन प्रशासन के प्रति विश्वास और मज़बूत बने। इसी प्रकार उन्होंने कलेक्टर जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन पोर्टल, जन शिकायत के विभागों में लंबित सभी प्रकरणों को भी तत्परता से निराकृत करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, सीईओ जिला पंचायत दिनेश नाग, संयुक्त कलेक्टर मनोज बजारे, ओंकार यादव, सहित सभी एसडीएम एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रिक्त निजी भूखण्डों की गंदगी, शहर की स्वच्छता को कर रही प्रभावित

चालू रोड में बिजली का खम्भा काटकर वाहन में लोड कर चलते बने

कोरबा, शहर व जिले भर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के दावों के बीच चोरों ने दुस्साहसिक तरीके से चालू रोड में बिजली का खम्भा काटा और वाहन में लोड कर चलते बने। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वारदात रविवार रात की बताई जा रही है। वीडियो में साफदिख रहा है कि एक पिकअप गाड़ी आती है, कुछ 4-5 लोग उतरकर कटर मशीन से बिजली का एक खम्भा को काटते हैं और आराम से ले जाते हैं। यहां पर और भी खम्भे पड़े हुए हैं जिनमें से एक को दो टुकड़े

में काटा गया। वारदात तब हुई, जबकि इस दौरान सड़क पर आवाजाही बनी थी। त्योहारी सीजन होने के कारण घटना स्थल से चंद दम दूर पावर हाउस रोड चैक पर जवानों की तैनाती रहती है। हालांकि,वारदात के वक्त इनकी मौजूदगी थी या नहीं,स्पष्ट नहीं है लेकिन अर्ध निर्मित मल्टिप्लेक्स के पास विद्युत सबस्टेशन के निकट रखे गए खम्भों से की गई इस वारदात ने कबाड़ियों और कबाड़ चोरों, लोहा चोरों के मन से पुलिस और कानून का भय खत्म होते जाने की पुष्टि जरूर कर दी है।

बताते चलें कि हाल फ़िलहाल के दिनों में कोतवाली सहित विभिन्न थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिलों,बाइक की चोरी की लगातार वारदातें हुई हैं-हो रही है जिन पर फ़िर भी दर्ज

की गई है, लेकिन चोरी के इन मोटरसाइकिलों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चोरी के वाहनों को काट-पीट कर बराबर कर कबाड़ में खपा दिया गया हो..! इससे पहले भी इस तरह के मामले पुलिस ने जरूर पकड़े हैं जिसमें चोरी किए गए वाहनों को काटकर कबाड़ में बेचने की तैयारी थी। इसके अलावा चोरी की छुटपुट वारदातें हो रही हैं जिनमें से कई मामलों में एफ़्भाईआर दर्ज नहीं कराई जाती और न ही कोई शिकायत होती है। नगर पालिक निगम द्वारा कराए गए सौंदर्यीकरण का लोहा भी चोरी होकर आखिर कहीं ना कहीं किसी न किसी कबड्डी के पास तो बेचा ही गया होगा! ट्रांसपोर्ट नगर चैक से लेकर शारदा विहार तिराहा तक

निगम द्वारा कराए गए सौंदर्यीकरण की रेलिंग से भी लोहा चोरी कर आसपास के क्षेत्र के कबाड़ी के पास बेचकर नशाखोरों ने नशा कर लिया, रेलिंग से लोहे की चोरी अभी भी चल रही है लेकिन सरकारी संपत्ति को चुराने वाले-खरीदने वाले पकड़ से दूर हैं। देखना होगा कि इस तरह से सरेआम खम्भा काटकर चुराने वाले कब तक पकड़ में आते हैं और इनका नेटवर्क भी पुलिस ध्वस्त कर पाती है या फिर एकाध कार्रवाई कर मामला ऐसे बस्ते में डाल दिया जाएगा। उंगे घटनाक्रमों को लेकर आम लोगों के बीच यह चर्चा भी आम है कि कप्तान की सख्ती के बावजूद भी थाना-चैकी स्तर पर कुछ लोगों की मिली भगत से सारा अवैध काम चल ही रहा है।

दैनिक मजदूर की सेवाएं की गई समाप्त

कोरबा,। प्राथमिक स्तर आदिवासी बालक आश्रम तुमान विकासखंड करतला में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत प्रतिपाल सिंह कंवर द्वारा शराब के नषे में ड्यूटी पर उपस्थित होने के कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसारप्राथमिक स्तर आदिवासी बालक आश्रम तुमान विकासखंड करतला में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत प्रतिपाल सिंह कंवर शराब का सेवन करके ड्यूटी पर उपस्थित होते हैं एवं कभी-कभी नषे की हालत में बच्चों के बिस्तर पर सोजाते हैं। उन्हें कई बार समझाईश देने के बाद भी उनके कार्यपैली में सुधार नहीं होने तथा आश्रम के बच्चों पर विपरित प्रभाव पड़ने को ध्यान में रखते हुए प्रतिपाल सिंह कंवर की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

मासूम बछड़े की डंडा से मारकर हत्या, दो युवकों पर अपराध दर्ज

कोरबा-पाली मामूली सी बात पर एक मासूम बछड़े की डंडा से मार-मार कर हत्या कर दी गई। बछड़ का वध करने वाले दो लोगों पर एफ्भाईआर दर्ज कर लिया गया है। प्राथी संजू यादव ग्राम लहरापारा बतरा में रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। उसने गाय-भैस का पालन भी किया है। उसके पास 03 गाय 04 बछड़, एवं 06 भैस, 07 पड़िया हैं जिन्हें 27 सितम्बर को सुबह 10.30 बजे चराने के लिये चनहा टिकरा ग्राम नगरही लेकर गया था। चराने के पश्चात अपने जानवरों को लेकर घर वापस लगभग शाम 4 बजे आया।



बदलता बस्तर, संवरता बस्तर

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

श्री अमित शाह जी का स्वागत-वंदन-अभिनंदन

कार्यक्रम : 4 अक्टूबर 2025

मुरिया दरबार

दोपहर 12: 00 बजे, सिरहासार भवन-जगदलपुर

बस्तर लोकोत्सव

दोपहर 1:00 बजे, लालबाग मैदान-जगदलपुर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

श्री अमित शाह
माननीय केंद्रीय गृह एवं
सहकारिता मंत्री



हमसे जुड़ने के लिए
QR CODE स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर...



Visit us : [f ChhattisgarhCMO](#) [X ChhattisgarhCMO](#) [@ ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [f DPRChhattisgarh](#) [X DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक प्रेमेश्वर अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राइवेट लि., जयसंतोष चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेश्वर अग्रवाल।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)